जन जन की बात जन जन तक

साप्ताहिक

जन जन विचार

সাপ্তাহিক

ৰাইজৰ কথা ৰাইজৰ মাজলৈ

জন জন বিচাৰ

WEEKLY TRILINGUAL NEWSPAPER

Language : Hindi, Assamese & English

WEBSITE : www.janjanvichar.in

VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

JAN JAN VICHAR

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 28 August 2026 :: Year-1 Vol-33 Issue-12 ::शुक्रवार। 28 अगस्त 2026। शक संवत 1948। श्रावण। शुक्ल। पूर्णिमा। :: पृष्ठ-20। मूल्य - 15 रुपए

जन चिंतन

धनेश्वर चौधरी

मनुस्मृति पर सियासत

मनुस्मृति का नाम आते ही राजनीति गरम हो जाती है। कोई इसे सामाजिक अन्याय का प्रतीक बताता है तो कोई इसके नाम पर अपनी वैचारिक राजनीति चमकाने लगता है। लेकिन सवाल सीधा है-क्या देश की राजनीति अब हजारों साल पुराने ग्रंथों के चुनिंदा श्लोकों के सहारे वोट मांगेगी?

राहुल गांधी मनुस्मृति पर सवाल उठाते हैं। यह उनका राजनीतिक अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी प्राचीन ग्रंथ का मूल्यांकन केवल उन अंशों से किया जाएगा जो आज की राजनीतिक बहस के लिए सुविधाजनक हों? यदि किसी श्लोक में स्त्री या किसी वर्ग के प्रति आपत्तिजनक व्यवस्था है, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ यह भी बताना होगा कि उसी ग्रंथ में स्त्री-सम्मान और सामाजिक कर्तव्यों से जुड़े शेष पृष्ठ 2 पर

खतरा अभी बाकी चीन ने चेताया

नई दिल्ली। चीन-नेपाल सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ से अभी तबाही का मंजर थमा भी नहीं है कि एक नई और बड़ी आपदा का खतरा मंडराने लगा है। चीन ने चेतावनी दी है कि नेपाल सीमा के पास मलबे से बनी एक बैरियर झील कभी भी टूट सकती है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक, झील में गुरुवार सुबह तक करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और पानी झील से बाहर निकलना शुरू हो गया है। अगले 72 घंटों में करीब 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंचने का अनुमान है। यह झील छोचेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम के पास, ग्यिरोंग से करीब 18 किलोमीटर ऊपर बनी है। लेंडे नदी में भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान और मलबा जमा होने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हुआ और उसके पीछे पानी जमा होकर झील का रूप ले चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि यह प्राकृतिक अवरोध अचानक टूट गया तो उसके पीछे जमा पानी और मलबा कितनी तेजी से नीचे की ओर जाएगा। ऐसी स्थिति में अचानक आने वाली बाढ़ पहले से प्रभावित नदी घाटियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।

नेपाल में जलप्रलय

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

469 लोगों की मौत 1,400 से ज्यादा लापता

हिमालय की ऊंची चोटियों पर प्रकृति के एक झटके ने नेपाल से लेकर भारत तक चिंता की नई लहर पैदा कर दी है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में आए भूकंप के कुछ ही मिनट बाद हिमस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने नेपाल-चीन सीमा से लगे इलाकों में भारी तबाही मचा दी। तेज बहाव और मलबे ने रास्ते में आने वाली बस्तियों, पुलों, सड़कों और जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस आपदा में करीब 469 लोगों की मौत हुई है और 1,400 से अधिक लोग लापता हैं। इनमें लगभग 290 भारतीय बताए जा रहे हैं।

सबसे गंभीर चिंता कैलास-मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीयों को लेकर है। सीमा क्षेत्र में संचार और सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित होने के कारण राहत और खोज अभियान चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में लापता लोगों की वास्तविक संख्या और नुकसान का पूरा आकलन आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो सकेगा।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सुबह करीब नौ बजे भोटेकोशी नदी में अचानक पानी बढ़ा। नेपाल-चीन सीमा के पास लेंडे नदी में बर्फ, चट्टानों और मलबे के खिसकने से पैदा हुई बाढ़ ने तिमुरे और आसपास के क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद पानी और मलबा त्रिशूली नदी तक पहुंचा और देखते ही देखते नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहुं और नवलपरासी तक इसका असर दिखाई देने लगा।

यह सामान्य बारिश या नदी में आई बाढ़ नहीं थी। पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और बर्फ नीचे की ओर आया, जिसने रास्ते में मौजूद ढांचों को ध्वस्त करने की क्षमता कई गुना बढ़ा दी।

नेपाल के विदेश मंत्री के अनुसार भूकंप के कुछ ही मिनट बाद अचानक बाढ़ की सूचना मिली। शुरुआती वैज्ञानिक आकलन में यह संभावना सामने आई है कि भूकंप के झटकों से ऊंचाई वाले क्षेत्र में ग्लेशियर या बर्फ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और उसने नदी में अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा पहुंचा दिया।

हालांकि आपदा का अंतिम वैज्ञानिक कारण अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है। यही सावधानी जरूरी है, क्योंकि हिमालय में भूकंप, ग्लेशियर झील, हिमस्खलन और भारी शेष पृष्ठ 3 पर

हमारी वजह से नहीं आई बाढ़, भड़का चीन

जन जन विचार
...✍ काठमांडू/बीजिंग

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और मलबे के सैलाब को लेकर चीन और नेपाल के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। नेपाल की ओर से चीन में बने एक कथित प्राकृतिक बांध के टूटने को तबाही की वजह बताए जाने पर चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

नेपाल स्थित चीनी दूतावास ने कहा कि

26 अगस्त की सुबह भूकंप या भूकंप जैसी गतिविधि के कारण ग्लेशियर धंसने की घटना हुई। इसके बाद बड़ी मात्रा में मलबा और कीचड़ नीचे की ओर बहा, जिससे नेपाल-चीन सीमा के ग्यिरोंग-रसुवागढ़ी क्षेत्र में भारी तबाही हुई। चीन ने नेपाल के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि आपदा के समय आरोप लगाने के बजाय दोनों देशों को राहत और बचाव कार्यों पर ध्यान देना चाहिए।

नेपाल की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक, ल्हेंदे नदी का बहाव मलबे के कारण बाधित हुआ था। इसके बाद अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव आया, जिसने रसुवागढ़ी के तिमुरे क्षेत्र में कई बस्तियों, सड़कों और इमारतों को नुकसान पहुंचाया।

रोहा में 'नामघर तीर्थयात्रा-2026' का शुभारंभ

जन जन विचार
...✍ रोहा

रोहा समष्टि कंठमंच की ओर से सप्ताहव्यापी 'नामघर तीर्थयात्रा-2026' का शुभारंभ पूर्व टोपाकुची स्थित नामघर से भक्तिमय वातावरण में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत नाम-कीर्तन, बरगीत और सत्रीया नृत्य की प्रस्तुतियों के साथ की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूरे क्षेत्र को नाम-कीर्तन से गुंजायमान कर दिया।

कंठमंच के सचिव जतिन जोनाक के संचालन में आयोजित शुभारंभ समारोह में नगांव के जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने नामघर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया और कंठमंच की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को नामघर और अपनी आध्यात्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर विशिष्ट बांसुरी वादक एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित दिलीप हीरा तथा लगातार 24 घंटे छह शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली तुष्टिमना नाथ को 'समष्टि गौरव सम्मान' से सम्मानित किया गया। जिला आयुक्त ने दोनों को फूलाम गामोछा और स्मृति-चिह्न प्रदान किया। कई अन्य कलाकारों का भी फूलाम गामोछा पहनाकर अभिनंदन किया गया।

कंठमंच के सचिव जतिन जोनाक ने बताया कि यात्रा के दौरान रोहा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न नामघरों में जाकर माथा टेकने के साथ आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में नाम-प्रसंग, भक्तिमय संगीत, आध्यात्मिक चर्चा, सामाजिक जागरूकता और कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी।

गरीब मेधावी विद्यार्थियों का डॉक्टर बनने का सपना अब होगा आसान

ढेकियाजुली में सितंबर से शुरू होगी नि:शुल्क 'सुपर-30' नीट कोचिंग

जन जन विचार
...✍ ढेकियाजुली

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी का नि:शुल्क अवसर मिलेगा। परमानंद-इंदुमती सिंघल फाउंडेशन की ओर से ढेकियाजुली में 'सुपर-30' नाम से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत सितंबर के पहले सप्ताह में होने की तैयारी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा ढेकियाजुली के विधायक अशोक सिंघल ने भोटपाड़ा स्थित विधायक सेवा केंद्र में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कमी नहीं है, लेकिन महंगी कोचिंग के कारण कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी नहीं कर पाते। 'सुपर-30' के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मार्गदर्शन और व्यवस्थित तैयारी का अवसर दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि यह पहल केवल ढेकियाजुली तक सीमित नहीं रहेगी। गोलकगंज, धुबड़ी, गौरीपुर, सिपाझार, मंगलदै और बरसोला सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी नि:शुल्क प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है। जोरहाट और शिवसागर में भी इस योजना के विस्तार पर विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा भोटपाड़ा स्टेडियम में करीब 400 युवक-युवतियों को भारतीय सेना, असम पुलिस और एसएसएससी जीडी जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। प्रशिक्षण में शारीरिक दक्षता के साथ लिखित परीक्षा की तैयारी पर भी जोर दिया जा रहा है।

राशिफल

28 अगस्त से 3 सितंबर, 2026।। विक्रम संवत 2083-**मास** : श्रावण, **पक्ष** : शुक्ल, **तिथि** :पूर्णिमा

मेष : यह सप्ताह आपके लिए उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। आर्थिक मामलों में लाभ हो सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ : मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर सामने आ सकते हैं। धन संबंधी स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

मिथुन : सप्ताह की शुरुआत व्यस्तता के साथ होगी, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियाँ आपके पक्ष में आएँगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।

कर्क : करियर के लिहाज से सप्ताह सकारात्मक रहेगा। नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि खर्च बढ़ सकता है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

सिंह : आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। नौकरी-व्यवसाय में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण योजना में सफलता मिलने की संभावना है। यात्रा के योग बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार में सम्मान बढ़ेगा।

कन्या : इस सप्ताह आपकी मेहनत रंग लाएगी। कार्यक्षेत्र में सफलता और आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारी आपके लिए भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है। परिवार में वातावरण अच्छा रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।

तुला : सप्ताह आपके लिए संतुलित और सकारात्मक रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में नई संभावनाएँ दिखाई देंगी। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक : आर्थिक दृष्टि से सप्ताह लाभदायक रह सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी। पुराने विवाद समाप्त होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव और अधिक काम से बचना उचित होगा।

धनु : करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। नौकरी बदलने या नई योजना शुरू करने का विचार सफल हो सकता है। यात्रा लाभदायक रहेगी। आर्थिक लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा।

मकर : सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में सावधानी से निर्णय लें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। किसी पुराने काम के पूरा होने से राहत मिलेगी।

कुंभ : नई योजनाओं और नए कार्यों के लिए समय अनुकूल है। नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आपकी रचनात्मकता और मेहनत की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें और अनावश्यक बहस से बचें।

मीन : यह सप्ताह कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ेंगे। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या अवसर प्राप्त हो सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आराम और दिनचर्या पर ध्यान दें।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

28 अगस्त (शुक्रवार) : रक्षाबंधन, संस्कृत दिवस
29 अगस्त (शनिवार) : अशून्यशयन व्रत
30 अगस्त (रविवार) : विंध्याचली भीमचंडी देवी जयंती
31 अगस्त (सोमवार) : संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत
2 सितंबर (बुधवार) : हलषष्ठी व्रत

●ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

पृष्ठ 1 का शेषांश...

मनुस्मृति पर सियासत

दूसरे विचार क्या हैं।

दूसरी तरफ मनुस्मृति के नाम पर आंख मूंदकर बचाव करने वालों को भी जवाब देना होगा। इतिहास कोई धार्मिक ढाल नहीं, जिसे जरूरत पड़ने पर सामने कर दिया जाए और असुविधाजनक सवाल आते ही छिपा लिया जाए। डॉ. अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। उनका संघर्ष सामाजिक भेदभाव के खिलाफ था। लेकिन बाद की संवैधानिक बहसों में उन्होंने प्राचीन स्मृतियों में महिलाओं के संपत्ति अधिकार से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख भी किया। इतिहास की यही जटिलता आज की नारेबाजी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। असल खतरा मनुस्मृति नहीं, मनुस्मृति की अधूरी व्याख्या पर होने वाली वोट की राजनीति है। देश को न अंधभक्ति चाहिए, न अंधविरोध। संविधान हमारा वर्तमान है और समानता हमारा भविष्य। राजनीतिक दल अगर सचमुच सामाजिक न्याय चाहते हैं तो पुराने ग्रंथों पर बयानबाजी छोड़कर आज की महिलाओं, दलितों और वंचितों के अधिकारों पर ठोस काम करके दिखाएं।

इतिहास के पन्ने जलाकर या उन्हें चुनावी मंच पर लहराकर राजनीति आसान हो सकती है, लेकिन समाज का भविष्य नहीं बनता।

धन दिशा

सोना : निवेश है या सिर्फ सजावट

त्योहारों का मौसम आते ही घर में बात होने लगती है, 'इस बार सोना लेना है।' दिवाली पर सोने की खरीद एक परंपरा है, और परंपराएं अच्छी होती हैं। लेकिन सवाल यह है- क्या गहनों के रूप में खरीदा सोना एक अच्छा निवेश भी है?

सच यह है कि सोने के गहने खरीदते वक्त आप सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज भी देते हैं, जो अक्सर 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक होता है। बेचते वक्त यह चार्ज वापस नहीं मिलता। यानी गहना खरीदते ही आपका निवेश पहले दिन से घाटे में शुरू होता है।

तो फिर सोने में निवेश कैसे करें? अगर सोने को निवेश की तरह देखना है, तो दो सबसे सही और सेबी नियंत्रित तरीके हैं-गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ। दोनों सरकारी नियामक सेबी के दायरे में आते हैं, इसलिए इनमें आपके पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित है।

गोल्ड म्यूचुअल फंड : शुरुआती निवेशक के लिए बेहतर। इसमें डीमैट खाते की जरूरत नहीं। आप अपने बैंक खाते से सीधे एसआईपी शुरू कर सकते हैं- सिर्फ 500 रुपए महीने से। यह फंड खुद गोल्ड ईटीएफ में निवेश करता है, इसलिए कीमत सोने के बाजार भाव से जुड़ी रहती है। नए निवेशकों के लिए यह सबसे सरल और सुरक्षित विकल्प है।

गोल्ड ईटीएफ : अनुभवी निवेशक के लिए। इसके लिए डीमैट और ट्रेडिंग खाता होना जरूरी है। यह शेयर बाजार में सोने की कीमत से जुड़ी यूनिट की तरह काम करता है। खर्च थोड़ा कम है, लेकिन इसे खरीदने-बेचने के लिए बाजार का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए।

'डिजिटल गोल्ड' से सावधान : कुछ ऐप्स 'डिजिटल गोल्ड' बेचते हैं जिसे सेबी या आरबीआई में से कोई नियामक नियंत्रित नहीं करता। इन पर निवेशक सुरक्षा का कोई कानूनी ढांचा नहीं है। सेबी ने खुद इन उत्पादों को लेकर जनता को सावधान किया है। इनसे दूर रहें।

पोर्टफोलियो में कितना सोना हो? कुल निवेश का 10-15 प्रतिशत सोने में रखना समझदारी है। यह बाजार की गिरावट के समय एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। लेकिन इससे ज्यादा सोने में लगाना भी सही नहीं - सोने पर नियमित आमदनी नहीं होती।

सोना हमेशा से भारतीय परिवारों की भावना का हिस्सा रहा है। गहने जरूर खरीदें, लेकिन उसे निवेश न समझें। निवेश के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड चुनें, सेबी का नियंत्रण, एसआईपी की सुविधा, और सोने का फायदा- सब एक साथ।

अगले हफ्ते : 80 सी- टैक्स बचाने का सही तरीका, और जो गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं।

इस कॉलम के लिए आपका कोई सवाल है? हमें भेजिए

-कोमल जैन

पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, संस्थापक, वेल्थप्लायर्स- मो. 9004510577

असम में कृषि विकास की नई राह बनेगी सिंचाई : पीयूष

जन जन विचार ...✍ गुवाहाटी

पांच वर्षों में 7,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य खेतों तक पानी पहुंचाने पर सरकार का जोर

असम सरकार ने कृषि क्षेत्र को नई गति देने के लिए सिंचाई व्यवस्था के विस्तार को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। कृषि एवं सिंचाई मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि राज्य में कृषि विकास के अगले चरण की आधारशिला मजबूत सिंचाई व्यवस्था होगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में सिंचाई विभाग के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने का है।

सिंचाई विभाग की प्रगति की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाना है। इसके लिए बड़े और अधिक प्रभावी सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के साथ मौजूदा योजनाओं की कार्यक्षमता बढ़ाई जाएगी।

हजारिका ने अधिकारियों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि धन की उपलब्धता के बावजूद योजनाओं में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग को आवंटित हर रुपए का परिणाम खेतों तक पानी पहुंचने के रूप में दिखाई देना चाहिए।

मंत्री के अनुसार, अगले पांच वर्षों में प्रस्तावित 7,000 करोड़ रुपए का खर्च पिछले पांच वर्षों में हुए व्यय की तुलना में करीब तीन गुना अधिक है। सरकार सिंचाई प्रणालियों में अनावश्यक जल-ग्रहण बिंदुओं को कम करने और संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग पर भी ध्यान देगी।

सरकार का मानना है कि सिंचाई का विस्तार होने से किसानों को खेती के लिए अधिक भरोसेमंद जलस्रोत मिलेगा, कृषि भूमि का बेहतर उपयोग संभव होगा और राज्य में खेती का दायरा बढ़ेगा।

मेघालय में रासायनिक खाद से मुक्ति की तैयारी

जन जन विचार ...✍ शिलांग

मेघालय सरकार राज्य में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को धीरे-धीरे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने विधानसभा में कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य को देश में जैविक खेती के सबसे व्यापक क्षेत्रों में शामिल करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रासायनिक खाद को बढ़ावा देने के बजाय किसानों को इसके इस्तेमाल से दूर करने की नीति पर काम कर रही है। इसके लिए जैविक खाद, मिट्टी की जांच और जैविक प्रमाणीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'हम बदलाव के दौर में हैं और उम्मीद है कि एक दिन राज्य में रासायनिक खाद की जरूरत नहीं रहेगी।'

विधानसभा में उर्वरकों की उपलब्धता और कृषि उपज के दाम को लेकर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने जुलाई में पत्तागोभी की कीमतों में आई भारी गिरावट का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जुलाई में कीमत करीब 2 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी, जो अब बढ़कर 20 से 25 रुपए प्रति किलो हो गई है। संगमा ने कहा कि जुलाई में कीमतों में गिरावट का एक प्रमुख कारण पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से सब्जियों की अधिक आपूर्ति रही।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

नेपाल में जल प्रलय

वर्षा-इन सभी का संयुक्त प्रभाव अचानक विनाशकारी बाढ़ में बदल सकता है।

सबसे बड़ा सवाल : क्या हिमालय विकास के दबाव में है?

इस त्रासदी ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्र में तेजी से हो रहे निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेपाल और तिब्बत दोनों ही क्षेत्रों में सड़क, सुरंग, जलविद्युत और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार हो रहा है। हिमालय की भौगोलिक संरचना अत्यंत नाजुक है और यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से भी संवेदनशील माना जाता है।

ऐसे इलाके में किसी भी बड़ी परियोजना का मूल्यांकन केवल आर्थिक लाभ के आधार पर नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या परियोजनाओं के निर्माण से पहले भूकंपीय जोखिम, ग्लेशियर टूटने की संभावना, अचानक बाढ़ और नदी के प्राकृतिक प्रवाह का पर्याप्त अध्ययन किया जा रहा है?

रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने इस घटना को हिमालय में बड़े बांधों और परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों के संदर्भ में देखने की जरूरत बताई है। हालांकि किसी विशेष परियोजना को इस बाढ़ का प्रत्यक्ष कारण बताना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस आपदा ने हिमालयी क्षेत्र में बड़े जलविद्युत ढांचों की सुरक्षा और संभावित सीमा-पार प्रभावों पर बहस जरूर तेज कर दी है।

नेपाल के बाद अब भारत की चिंता क्यों बढ़ी? नेपाल की नदियां भारत के मैदानी इलाकों की नदियों से सीधे जुड़ी हैं। इसलिए हिमालय में होने वाली बड़ी प्राकृतिक आपदा का असर केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहता। नेपाल में जलस्तर बढ़ने के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

भारत के लिए चुनौती दोहरी है-एक ओर नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी और दूसरी ओर सीमा पार से आने वाले अतिरिक्त पानी के कारण भारतीय नदियों में बढ़ते जलस्तर की निगरानी।

विशेष रूप से बिहार के लिए यह स्थिति गंभीर है, क्योंकि राज्य की कई प्रमुख नदियां नेपाल से निकलती हैं। मानसून के दौरान पहले से ऊफनाई नदियों में अचानक अतिरिक्त पानी आने पर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ सकता है।

नेपाल सरकार ने नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस और नेपाल पुलिस को राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया है। सेना ने 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं और कई स्थानों पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लेकिन कई प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर उतारना भी मुश्किल हो रहा है।

भारत ने भी सहायता का हाथ बढ़ाते हुए मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के तहत 10 टन राहत सामग्री और आवश्यक दवाएं नेपाल भेजी हैं।

आपदा ने नेपाल के ऊर्जा ढांचे को भी झटका दिया है। नुवाकोट और रसुवा जिलों में कई चालू और निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इससे केवल बिजली उत्पादन प्रभावित होने का खतरा नहीं है, बल्कि यह सवाल भी उठता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं को प्राकृतिक आपदाओं से कितना सुरक्षित बनाया गया है।

संपादकीय

राहुल की नारी-मुक्ति व प्रियंका

राहुल गांधी जब मंच से कहते हैं कि महिला किसी की संपत्ति नहीं, वह स्वयं की मालिक है, तो सुनने में यह बात बेहद प्रभावशाली लगती है। लेकिन राजनीति में असली परीक्षा नारों की नहीं, उनके अपने जीवन और विचारों की होती है।

राहुल ने मनुस्मृति को महिलाओं की स्वतंत्रता के विरोध का प्रतीक बताया और पितृसत्ता को तोड़ने का आह्वान किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं को कानून, शिक्षा, संपत्ति, रोजगार और राजनीति में पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। सवाल यह है कि क्या हर पारंपरिक भूमिका अपने आप में पितृसत्ता का प्रमाण है?

यहीं राहुल के सामने सबसे कठिन सवाल खड़ा होता है-प्रियंका गांधी का जीवन।

एक ही परिवार में जन्मे भाई-बहन, समान राजनीतिक विरासत, लेकिन बिल्कुल अलग जीवन-यात्रा। राहुल 33 वर्ष की उम्र में संसद पहुंचे और दशकों तक राजनीति में प्रयोग करने, असफल होने और फिर खड़े होने का अवसर मिला। प्रियंका ने विवाह किया, मां बनीं, परिवार और राजनीति दोनों से जुड़ी रहीं और 52 वर्ष की उम्र में संसद पहुंचीं।

क्या यह अंतर पितृसत्ता का परिणाम था? संभव है। लेकिन यह भी संभव है कि यह व्यक्तिगत पसंद और परिस्थितियों का परिणाम हो। किसी महिला का विवाह और मातृत्व चुनना उसकी स्वतंत्रता की हार मान लेना भी उतना ही गलत है जितना उसे इन भूमिकाओं तक सीमित कर देना।

राहुल की बात का सबसे मजबूत हिस्सा यही होना चाहिए कि महिला को अपने जीवन का फैसला खुद करने का अधिकार मिले। लेकिन यह सिद्धांत तब और विश्वसनीय होगा, जब राजनीति में रिश्तों, परिवार और परंपरा को बिना जांचे-परखे खलनायक बनाने के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जटिलताओं को भी स्वीकार किया जाए।

मनुस्मृति पर बहस आसान है, लेकिन अपने घर के आईने में वही सवाल देखना कहीं ज्यादा कठिन।

हंगर मार्च के शहीदों को नमन

मणिपुर के 1965 के हंगर मार्च के शहीदों को याद करना केवल पुष्पांजलि देने की रस्म नहीं होनी चाहिए। उन युवाओं ने चावल की कृत्रिम कमी और प्रशासनिक विफलता के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका संघर्ष एक सवाल छोड़ गया था-सरकार जनता के प्रति कितनी जवाबदेह है? आज 61 साल बाद मणिपुर फिर उसी सवाल के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार संकट कहीं गहरा है। हिंसा ने समाज को बांट दिया है, हजारों परिवार विस्थापित हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध आवाजाही तक चुनौती बन गई है। एनआरसी और जनगणना जैसे संवेदनशील मुद्दों ने अविश्वास को और बढ़ाया है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयास से होना चाहिए, उन्हें जातीय और क्षेत्रीय चश्मे से देखा जा रहा है। विस्थापित परिवार चाहे किसी भी समुदाय के हों, उनका दर्द एक जैसा है। उन्हें सुरक्षा, घर, भोजन, शिक्षा और सम्मान के साथ लौटने का अधिकार है। सरकार को अब घोषणाओं से आगे बढ़कर गांव-दर-गांव पुनर्वास की स्पष्ट समयसीमा तय करनी होगी। राजमार्ग किसी समुदाय की जागीर नहीं हैं। हर कानूनसम्मत नागरिक को बिना भय यात्रा करने का अधिकार मिलना चाहिए।

जर्जर शिक्षा व्यवस्था

जन जन विचार
...✍ ललित गर्ग

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक, टूटती दीवारें और घटते सरकारी स्कूल-क्या शिक्षा के बिना 2047 का सपना पूरा होगा? दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गौरव का विषय हैं। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे यदि हम सरकारी स्कूलों की ओर देखें तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है-ऐसा भारत जहां हजारों बच्चे आज भी पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस शिक्षा-व्यवस्था पर विकसित भारत की नींव रखी जानी है, उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो 2047 का भारत कितना मजबूत होगा? सरकारी आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं। यूडीआईएसई प्लस 2024-25 के अनुसार देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है और इन स्कूलों में करीब 33.77 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को कई कक्षाओं, अनेक विषयों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा संभालनी पड़ रही है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों के भविष्य की कहानी है, जिनके लिए सरकारी स्कूल शिक्षा का सबसे सुलभ और कई बार एकमात्र माध्यम हैं।

विडंबना यह है कि उसी देश में हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल संस्थानों और अत्याधुनिक शिक्षण परिसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव के उस बच्चे की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो टूटी छत के नीचे बैठकर भविष्य के सपने देख रहा है। कहीं शिक्षक एक है और कक्षाएं पांच। कहीं विद्यालय भवन जर्जर है, कहीं पानी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं बिजली और पंखे नहीं। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों को अधिक शिक्षक, बेहतर भोजन, पेयजल, पंखे और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। फतेहपुर में तो लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने जर्जर कक्षाओं, रिसती छतों और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया। यह स्थिति केवल किसी एक राज्य अथवा किसी एक सरकार की विफलता नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता तो भाषणों में दी गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान नहीं मिला। शिक्षा विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी व्यवस्था है, बजट है, योजनाएं हैं, समितियां हैं, निरीक्षण तंत्र है-फिर भी एक शिक्षक वाले एक लाख से अधिक स्कूल कैसे बने रहे? यह सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र से पूछा जाना चाहिए।

निश्चित रूप से तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। यूडीआईएसई प्लस के अनुसार 2024-25 में देश में कुल 14.71 लाख स्कूल, करीब 24.69 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 10.13 लाख है, जबकि निजी मान्यता प्राप्त स्कूल करीब 3.40 लाख हैं। सरकार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 2023-24 के 1,10,971 से घटकर 2024-25 में 1,04,125 हुई है और कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हुआ है। इन सुधारों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्हें अंतिम उपलब्धि मान लेना आत्मसंतोष होगा। क्योंकि शिक्षा की असली कसौटी भवन, कंप्यूटर या आंकड़े नहीं, बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके भविष्य का निर्माण है।

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखती है। 2014-15 में देश में 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2024-25 में घटकर 10.13 लाख रह गए। इसके विपरीत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई। यह परिवर्तन केवल स्कूलों की संख्या का उतार-चढ़ाव नहीं है, यह अभिभावकों की बदलती पसंद और सरकारी शिक्षा में घटते विश्वास का संकेत भी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब सरकार के पास भवन है, जमीन है, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, वेतन देने की क्षमता है और विशाल प्रशासनिक तंत्र है, तब सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से पीछे क्यों हैं? निजी स्कूलों की आलोचना करना आसान है, लेकिन यह भी देखना होगा कि अभिभावक अपनी सीमित आय में फीस देकर भी निजी स्कूल क्यों चुन रहे हैं। इसका उत्तर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, अनुशासन, नियमितता, अंग्रेजी एवं तकनीकी शिक्षा, अभिभावक संवाद और सीखने के वातावरण में छिपा है। एसीईआर के आंकड़े भी इस अंतर को रेखांकित करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कक्षा 3 के बच्चों में कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाने वालों का अनुपात सरकारी स्कूलों में 23.4 प्रतिशत था, जबकि निजी स्कूलों में 35.5 प्रतिशत। कक्षा 5 में भी सरकारी स्कूलों का आंकड़ा 44.8 प्रतिशत और निजी स्कूलों का 59.3 प्रतिशत रहा। यानी समस्या केवल स्कूल भवन की नहीं, सीखने के परिणामों की भी है।

इसी के समानांतर उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तस्वीर भी चिंता पैदा करती है। पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता, भर्ती में देरी और युवाओं के आंदोलनों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। 2026 में परीक्षा संबंधी विवादों ने विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों में असंतोष को व्यापक बनाया। इसका अर्थ यह है कि समस्या शिक्षा-व्यवस्था के निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक फैली हुई है। प्राथमिक स्कूल में कमजोर नींव, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता का संकट और उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता का सवाल-इन सबको अलग-अलग देखकर समाधान नहीं निकलेगा। सरकारी स्कूल वास्तव में भारत की सामाजिक समानता का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन स्कूलों में ग्रामीण परिवारों, श्रमिकों, गरीबों, वंचित वर्गों और निम्न आय वाले परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। यदि इन विद्यालयों की गुणवत्ता गिरती है तो सबसे अधिक नुकसान उसी वर्ग को होता है जिसके पास महंगे निजी स्कूलों का विकल्प नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूलों की बदहाली केवल शिक्षा का संकट नहीं, सामाजिक न्याय का संकट भी है।

यहां एक कठोर लेकिन सार्थक सुझाव पर विचार होना चाहिए-क्या जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चों के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को प्रोत्साहित अथवा अनिवार्य करने जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है? जब नीति बनाने वाले परिवार स्वयं उसी व्यवस्था का अनुभव करेंगे, तब शायद स्कूल की टूटी खिड़की, बंद शौचालय, शिक्षक की कमी और खराब मिड-डे-मील केवल फाइल की टिप्पणी नहीं रहेंगे, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव बन जाएंगे। शिक्षा को केवल मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म या मुफ्त पुस्तकों की योजनाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये आवश्यक हैं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना नहीं, उसे ज्ञान, विवेक, कौशल, संस्कार और आत्मविश्वास से संपन्न नागरिक बनाना है। जिस बच्चे को आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, उससे कल विकसित भारत के निर्माण में प्रभावी योगदान की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?

टीआरई-4 पर झुकी सरकार एक ही चरण में होगी परीक्षा

जन जन विचार
...✍ पटना

बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टीआरई-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा अब दो चरणों में नहीं, बल्कि एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। छात्र प्रतिनिधियों की प्रमुख मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े कुल 10 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति जताई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार शुरू से ही छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर रही है और उनके बेहतर भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के बाद टीआरई-4 को एकल चरण में कराने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की शिकायतों से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श के बाद सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति पटना हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में काम करेगी।

समिति के समक्ष विभिन्न परीक्षाओं को लेकर छात्रों की शिकायतें, सुझाव और आरोप रखे जा सकेंगे।

नगर परिषद सभापति सभी वादों पर फेल

पूर्व सभापति अंशुमान नंदन सिंह ने लगाया आरोप, मांगा इस्तीफा

जन जन विचार
...✍ संजय गुप्ता
शिवहर

नगर परिषद के पूर्व सभापति अंशुमान नंदन सिंह ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान सभापति राजन नंदन सिंह पर विकास कार्यों में विफल रहने और जनता से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले राजन नंदन सिंह ने प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय-जगदीश नंदन सिंह पथ की समस्या को दो वर्ष में दूर कर क्षेत्र को विकास की राह पर ले जाने का वादा किया था, लेकिन करीब तीन वर्ष दो महीने बीत जाने के बावजूद कार्य गुणवत्ता के अनुरूप पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने सभापति से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की।

पूर्व सभापति ने कहा कि वे नगर परिषद के सभी 26 वार्डों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं और विभिन्न विकास कार्यों की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने नल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए

कहा कि कई स्थानों पर काम संतोषजनक नहीं है। नगर परिषद में शामिल सात गांवों को ग्रामीण फीडर से बिजली मिलती है, जबकि बिजली बिल का भुगतान शहरी क्षेत्र की दर से करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सभापति की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई।

उन्होंने नाला निर्माण की गुणवत्ता और लेवलिंग पर भी सवाल उठाया। साथ ही आरोप लगाया कि कई योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार नहीं किया गया और शहरी आवास योजना के लाभुकों को भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। गरीब परिवारों के पक्के मकान निर्माण में भी कथित रूप से लापरवाही बरती जा रही है।

अंशुमान नंदन सिंह ने नगर परिषद कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्पष्ट नीति निर्धारण के अभाव में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर ऐसी सड़कों का निर्माण कराया गया, जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी। साफ-सफाई व्यवस्था पर भी उन्होंने नाराजगी जताई।

पूर्व सभापति ने कहा कि उनके कार्यकाल में ही बुडको के माध्यम से प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय-जगदीश नंदन सिंह पथ के निर्माण की योजना स्वीकृत कराई गई थी। उनके कार्यकाल में हाईमास्ट और स्ट्रीट लाइट भी लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान में इनके रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में अंधेरा रहता है।

उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही संकेत दिया कि आने वाले दिनों में वे विकास कार्यों और नगर परिषद की कार्यप्रणाली से जुड़े और भी मामलों का खुलासा करेंगे।

गंगा में मजदूरों से भरी नाव पलटी, छह लापता

भागलपुर के नवगछिया के राघोपुर में गंगा की तेज धारा में मजदूरों से भरी नाव पलट गई। नाव में सवार 18 मजदूरों में से 12 सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि छह के लापता होने की आशंका है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, गोताखोर और स्थानीय प्रशासन ने मोटरबोट की मदद से तलाश अभियान शुरू कर दिया। तेज बहाव के कारण राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है।

गंगा कटाव का मुद्दा अब टावर तक पहुंचा

वैशाली के राघोपुर में कटावरोधी काम शुरू नहीं होने से नाराज नगरगांवा निवासी रवि कुमार पहाड़पुर पश्चिमी के बजरंगबली चौक स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक ने मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बुलाने और कटावरोधी कार्य शुरू कराने की मांग की। सूचना मिलते ही राघोपुर और जुरावनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया। परिजनों को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले तेजस्वी यादव ने बहरामपुर में कटाव क्षेत्र का निरीक्षण किया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं होने से युवक नाराज था।

रिश्वत मांगने पर सहायक थानेदार निलंबित

गोपालगंज। पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर 3 हजार रुपए रिश्वत मांगने और कदाचार के आरोप प्रमाणित होने पर एसपी विनय तिवारी ने भोरे थाने के अपर थानाध्यक्ष सह पुलिस अवर निरीक्षक संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जांच में सामने आया कि आवेदक संजय कुमार से रिश्वत मांगी गई और राशि नहीं देने पर पुराने मामले का हवाला देकर पासपोर्ट सत्यापन में अनुचित कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, गोपालगंज रहेगा। एसपी ने भ्रष्टाचार और नियमविरुद्ध कार्रवाई पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पहले भी रिश्वत मामले में थानाध्यक्ष समेत चार लोगों को जेल भेजा गया था।

हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका

मुजफ्फरपुर के कांटी में एनटीपीसी के प्रतिबंधित क्षेत्र में 45 वर्षीय शंभू सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह बेटी के प्रसव की खबर मिलने पर अस्पताल जाने के लिए घर से निकले थे। उनका शव डाइक लैगून-1 की झाड़ियों में मिला। बदमाश उनका मोबाइल भी ले गए। परिजनों के अनुसार, शंभू और उनकी पत्नी को करीब एक महीने से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस धमकी और हत्या के बीच संबंध की जांच कर रही है।

समस्तीपुर में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग

समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के महथी बांध पर बुधवार देर शाम दो बाइक से आए पांच हथियारबंद बदमाशों ने युवक आदित्य वत्स उर्फ नवनीत पर करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग कर दी। तीन गोलियां पीठ, कमर और पैर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर किया गया। बताया गया कि आदित्य घरेलू सामान लेने गया था, तभी बदमाशों ने उसे घेरकर गोली मार दी। वारदात के बाद सभी हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हमले के कारणों और आरोपियों की पहचान का पता लगाया जा रहा है।

रोसड़ा की डीसीएलआर दो लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जन जन विचार
...✍ समस्तीपुर

समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) कंचन कुमारी झा को कथित तौर पर दो लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई रोसड़ा स्थित उनके सरकारी आवास पर की गई। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने आवास की तलाशी भी ली, जिसमें कथित तौर पर

करीब 13 लाख रुपए नकद बरामद होने की चर्चा है। हालांकि, नकद बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि निगरानी विभाग की विस्तृत जानकारी के बाद ही हो सकेगी।

मामला विभूतिपुर निवासी मनोज कुमार महतो के जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता का भूमि विवाद संबंधी मामला डीसीएलआर स्तर पर लंबित था। आरोप है कि मामले को उसके पक्ष में सुलझाने के बदले कंचन कुमारी झा ने दो लाख रुपए नकद के साथ एक वॉशिंग मशीन की भी मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मामले का सत्यापन कराया। शिकायत की पुष्टि होने के बाद ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई। गुरुवार सुबह करीब नौ बजे निगरानी विभाग की टीम दो वाहनों से रोसड़ा स्थित डीसीएलआर के सरकारी आवास पहुंची। टीम के साथ शिकायतकर्ता मनोज कुमार महतो भी मौजूद थे।

गंडक में बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

जन जन विचार
...✍ पटना

नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की आशंका के बीच बिहार में गंडक नदी से संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में संवेदनशील जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह सतर्क रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत सीतामढ़ी व शिवहर जैसे संवेदनशील जिलों के लिए तैयार किए गए माइक्रो प्लान की समीक्षा की गई। अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में राहत एवं चिकित्सा सेवाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहने देने को कहा गया।

स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, नवजात शिशुओं, बुजुर्गों और गंभीर रोगियों पर विशेष ध्यान देने की योजना बनाई है। दुर्गम क्षेत्रों में नौका एम्बुलेंस और नौका औषधालय की व्यवस्था की गई है, जिनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल कर्मी और प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों पर 102 एम्बुलेंस सेवा को चौबीसों घंटे अलर्ट रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 60 आवश्यक दवाओं और जीवनरक्षक टीकों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया गया है। इनमें सर्पदंश की दवा, एंटी-रेबीज वैक्सीन, ओआरएस, जिंक की गोलियां और अन्य जरूरी दवाएं शामिल हैं।

विभाग ने आशा और एएनएम के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं की सूची भी तैयार की है। जिन महिलाओं का प्रसव बाढ़ के दौरान संभावित है, उन्हें पहले से सुरक्षित स्वास्थ्य केंद्रों या प्रसव गृहों में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।

बाढ़ की स्थिति में पेयजल शुद्धिकरण और संक्रमण रोकने के लिए हैलाजोन की गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर और चूना भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। विभाग ने सभी संबंधित जिलों को लगातार निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अमेठी में बनी देश की पहली पूरी तरह स्वदेशी 'शेर' राइफल

जन जन विचार
...✍ लखनऊ/अमेठी

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरवा संयंत्र में देश की पहली पूरी तरह स्वदेशी एके-203 असॉल्ट राइफल तैयार की गई है। इसे 'शेर' नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस संस्करण में किसी विदेशी पुर्जे या कच्चे माल का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

यह राइफल भारतीय सेना की दशकों पुरानी 5.56 मिमी इंसास राइफल की जगह लेगी। भारत-रूस सहयोग से शुरू हुई परियोजना अब पूरी तरह भारतीय उत्पादन क्षमता तक पहुंच गई है। सेना के

लिए कुल 6,01,427 राइफलों की आपूर्ति का अनुबंध करीब 5,200 करोड़ रुपए में हुआ है।

कोरवा संयंत्र में शुरुआत में एके-203 का उत्पादन रूस से मिले तकनीकी हस्तांतरण के आधार पर हुआ था। शुरुआती चरण में विदेशी तकनीक और उपकरणों पर निर्भरता थी, लेकिन अब उत्पादन की पूरी श्रृंखला भारतीय उद्योग से जुड़ गई है। स्वदेशी राइफल का फायरिंग और बर्स्ट फायरिंग परीक्षण भी पूरा किया जा चुका है।

कंपनी का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले सेना को राइफलों की आपूर्ति करना है। वर्ष 2026 से उत्पादन क्षमता बढ़ाकर करीब 12 हजार राइफल प्रतिमाह करने की योजना है। आगे संयंत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाते हुए हर 100 सेकेंड में एक एके-203 तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

7.62 गुणा 39 मिमी क्षमता वाली यह आधुनिक असॉल्ट राइफल मजबूती, विश्वसनीयता और संचालन में आसानी के लिए विकसित की गई है। इसे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ आतंकवाद रोधी अभियानों में तैनात जवानों के प्रमुख व्यक्तिगत हथियारों में शामिल किया जाएगा।

विद्यालय निरीक्षण में सामने आई खामियां

शिवहर। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष बागी कौशल कुमार प्रियदर्शी ने टीम के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर एवं सरस्वती कोचिंग सेंटर, कुअमा का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय में 500 से अधिक नामांकित बच्चों के बावजूद 50 से कम विद्यार्थी उपस्थित मिले। बच्चों ने नियमित पढ़ाई नहीं होने और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। प्रधानाध्यापक से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर टीम ने नाराजगी जताई। जिलाध्यक्ष ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से फोन पर बात कर जांच एवं व्यवस्था सुधार की मांग की। मौके पर विजय राम, रजनीश जाटव, श्रवण कुमार, नितिन अरुण सहित अन्य मौजूद थे।

ईको की टक्कर से पिता-पुत्र की मौत

आगरा। मलपुरा थाना क्षेत्र में लालऊ पुल के पास तेज रफ्तार ईको गाड़ी ने स्कूटी सवार पिता-पुत्र को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में कागारौल निवासी पप्पू और उनके पुत्र सनी की मौत हो गई। दोनों सिकंदरा की जूता फैक्टरी में काम करते थे और रात की शिफ्ट के बाद घर लौट रहे थे। टक्कर के बाद दोनों कई फीट दूर जा गिरे। पुलिस उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक ईको छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। परिवार में मातम पसरा है।

पानी से भरे गड्ढे में डूबकर किसान मरा

वाराणसी। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के घियहां गांव में बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से किसान रामनाथ यादव (42) की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। रामनाथ खेत में खाद डालकर घर लौट रहे थे। खेत के पास पानी छूने के दौरान अचानक पैर फिसलने से वह गड्ढे में गिर गए और गहरे पानी में डूब गए। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। रामनाथ एक बेटा और एक बेटी के पिता थे। सूचना मिलने पर दिल्ली में रह रहे परिजन गांव पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भतीजे ने घटना की तहरीर दी है।

सड़क हादसे में गई युवक की जान

गाजीपुर। जमानिया में दाह संस्कार से घर लौट रहे 32 वर्षीय पंकज खरवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा बृहस्पतिवार देर रात करीब एक बजे विकास खंड तिराहा और स्टेट बैंक के पास हुआ। दिलदारनगर वार्ड-5 निवासी पंकज बलुआ घाट पर दाह संस्कार में शामिल होने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक सामने आए साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे में पंकज गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सात बहनों के इकलौते भाई की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

केले तोड़ने की सजा : बच्चों को बांधकर पीटा

दरभंगा। जमालपुर थाना क्षेत्र के ढंगा गांव में केले तोड़ने के आरोप में चार नाबालिग बच्चों को पिलर से बांधकर लाठी-डंडों से पीटने का मामला सामने आया है। आरोप पैक्स अध्यक्ष संजय यादव पर लगा है। बताया गया कि 25 अगस्त को चारों बच्चे खेलते हुए पैक्स अध्यक्ष के गोदाम के पास पहुंच गए थे। आरोप है कि बच्चों को पकड़कर घर ले जाया गया, जहां उन्हें रस्सी से पिलर में बांधकर पीटा गया। घटना की तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया। बच्चों के परिजनों ने विरोध किया तो उन्हें धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों के पहुंचने पर बच्चों को मुक्त कराया गया। जमालपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से आवेदन, तस्वीर और वीडियो मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

श्रीलंका से मैच ड्रॉ खेल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत पांचवें स्थान पर

जन जन विचार
...✍ कोलंबो

श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद भारतीय टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बड़ा फायदा नहीं मिल सका। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 51.52 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें स्थान पर बनी हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 80 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष पर अपना दबदबा कायम रखे हुए है।

कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम जीत के करीब पहुंचकर भी मुकाबला अपने नाम नहीं कर सकी। श्रीलंका

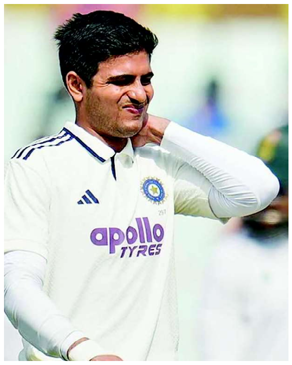

के सोनल दिनुशा ने दोनों पारियों में शानदार शतक लगाकर भारतीय गेंदबाजों को लंबे समय तक परेशान किया। भारत ने श्रीलंका को दोबारा बल्लेबाजी के लिए मजबूर किया था, लेकिन समय रहते पूरी टीम को आउट नहीं कर सका। इससे भारत को जीत के बजाय बराबरी से संतोष करना पड़ा।

इससे पहले गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हराया था। हालांकि दूसरा मुकाबला बराबरी पर छूटने के कारण भारत की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 80 प्रतिशत के साथ पहले, दक्षिण अफ्रीका 75 प्रतिशत के साथ दूसरे और न्यूजीलैंड 72.22 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। बांग्लादेश 55.56 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है।

भारत ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें पांच में जीत मिली है। श्रीलंका 33.33 प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर है। इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान क्रमश: सातवें, आठवें और नौवें स्थान पर हैं।

भारत के लिए आगे की राह आसान नहीं है। शीर्ष चार में जगह बनाने के लिए उसे आने वाले मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज करनी होगी। एक और बराबरी या हार उसकी अंतिम दौर में पहुंचने की उम्मीदों को कमजोर कर सकती है।

हॉकी विश्व कप : 52 साल बाद भारतीय महिलाओं ने हासिल किया 5वां स्थान

जन जन विचार
...✍ एम्सटेलवीन

विश्व कप में सिर्फ एक मैच हारने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी रखते हुए नवनीत कौर के दो गोल की मदद से पांचवीं रैंकिंग वाली जर्मन टीम को 3-1 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया जो पिछले 52 साल में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। विश्व रैंकिंग में नौवे स्थान पर काबिज भारत को इस टूर्नामेंट में एकमात्र पराजय का सामना ओलंपिक चैम्पियन सह मेजबान नीदरलैंड के हाथों (0-2) करना पड़ा था। दूसरे दौर के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया से गोलरहित ड्रॉ के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुई कोच शोर्ड मारिन की टीम ने जर्मनी के खिलाफ सारी कसर निकालते हुए आखिरी 17 मिनट में तीन गोल दागे।

भारत के लिए इशिका (43वां मिनट), नवनीत (44वां और 47वां) ने गोल दागे। जर्मनी के लिए लिन क्रिंग्स ने 59वें मिनट में एकमात्र गोल दागा। इसी जर्मन टीम ने टूर्नामेंट से पहले दो अभ्यास मैचों में भारत को हराया था।

क्लासीफिकेशन मैच में पहले 43 मिनट तक दोनों टीमों एक दूसरे को आजमाती रही लेकिन कामयाबी नहीं मिली और आखिरी सत्रह मिनट में भारत ने जबर्दस्त पासिंग, बेहतरीन फिनिशिंग और मजबूत रक्षण का प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। जर्मनी को मैच में पांच पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन भारतीय गोलकीपर और डिफेंस चट्टान की तरह अडिग रहा।

विश्व कप में पहली बार खेल रही 11 खिलाड़ियों के साथ उतरे कोच मारिन के साथ ड्रैग फ्लिक कोच ताइके ताकेमा और विश्लेषण कोच मथियास विला जीत के बाद उछलते नजर आए।

यह 1974 में अजिंदर कौर की अगुवाई में पहले विश्व कप में चौथे स्थान पर रहने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगले महीने होने वाले एशियाई खेलों से पहले इस प्रदर्शन से भारतीय टीम का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। पहले ही मैच में ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 2 -2 से ड्रॉ पर रोकने वाली भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6 -1 से हराया था लेकिन फिर इंग्लैंड से ड्रॉ खेला था।

एकमात्र पराजय दूसरे चरण में डच टीम के हाथों मिली लेकिन मेजबान ने दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर पर दागे थे। पांचवें मिनट में भारत ने पहला प्रयास किया जब नवनीत बायीं ओर से गेंद लेकर सर्कल के भीतर घुसी और दाहिनी ओर सलीमा को पास दिया लेकिन जर्मन गोलकीपर ने आगे की ओर बढ़कर रोक दिया। सलीमा ने पेनल्टी कॉर्नर की मांग की लेकिन अंपायर ने मना किया।

नौवें मिनट में जर्मनी की एम्मा डेविडस्मेयेर गेंद लेकर दाहिने ओर से अकेले आगे बढ़ी लेकिन गोल के सामने नियंत्रण नहीं रख सकी और शॉट लेने में नाकाम रही। पहला क्वार्टर खत्म होने से ठीक पहले शिल्पी डबास ने मिडफील्ड में नेहा को गेंद सौंपी जो उस पर नियंत्रण नहीं रख सकी। जर्मनी को 15वें मिनट में मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला जब इशिका ने एम्मा को सर्कल के भीतर बाधा पहुंचाई।

भारत ने इस पर रेफरल लिया लेकिन वीडियो अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला बरकरार रखा और भारत ने अपना रेफरल गंवा दिया। लिली स्टोफेलस्मा की ड्रैग फ्लिक को भारतीय गोलकीपर बिछू देवी ने बखूबी बचाया लेकिन रशर के पहले दौड़ने के कारण जर्मनी को लगातार दूसरा कॉर्नर मिला जिस पर वैरिएशन की कोशिश नाकाम रही। पहले पंद्रह मिनट में कोई टीम गोल नहीं कर सकी।

दूसरे क्वार्टर में चौथे मिनट में भारत ने पहला प्रयास किया जब मैदान के बीच से दीपिका ने गेंद नवनीत को सौंपी जिसने सर्कल पर लालरेम्सियामी को पास दिया लेकिन उसका शॉट गोलपोस्ट के बाहर से निकल गया। जर्मनी को इसी मिनट पलटवार में तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर पुश कमजोर होने से कामयाबी नहीं मिली। भारत के पास 22वें मिनट में फिर सुनहरा मौका था लेकिन दो कोशिशों के बावजूद उसे फिनिश तक नहीं ले जाया जा सका।

पहले नवनीत ने बायीं ओर से सीधा शॉट लिया जिसे जर्मन गोलकीपर फिंजा स्टार्क ने बायां पैर आगे करके रोक लिया लेकिन गेंद अभी भी डी के भीतर थी और गोल के दाहिने ओर सलीमा के पास गई जिनका प्रयास भी जर्मन डिफेंस ने नाकाम कर दिया और गेंद बाहर निकाल दी। ब्रेक तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी। ब्रेक के बाद भी दोनों टीमों में कोई तेजी नजर नहीं आई और मैच काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा।

इशिका 35वें मिनट में दाहिने फ्लैंक से अकेले गेंद लेकर आगे बढ़ी लेकिन सर्कल के पास पहुंचकर नियंत्रण खो दिया। इसके तीन मिनट बाद ज्योति को फिजियो की मदद से मैदान छोड़कर आना पड़ा जब उनका घुटना मुड़ गया। भारत को लगातार अच्छे प्रयासों का नतीजा 43वें मिनट में मिला जब नेहा से गेंद लेकर इशिका सर्कल के भीतर घुसी और रिवर्स हिट पर जर्मन गोलकीपर के ऊपर से गेंद गोल के भीतर डाल दी।

भारत को मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर अगले ही मिनट मिला जब नवनीत को सर्कल में बाधा पहुंची। नवनीत की स्लैप हिट रोके जाने से पहले गेंद डिफेंडर के पैर से टकराई जिससे भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस पर नवनीत ने गेंद को रोककर फिर उसी तकनीक से स्लैप लगाई और भारत के लिए दूसरा गोल दाग दिया।

नवनीत की शानदार ड्रिबलिंग के दम पर भारत को तीसरा गोल मिला जब जर्मन डिफेंडरों से घिरने के बावजूद उन्होंने गेंद पर से कब्जा नहीं गंवाया और गोलकीपर के पास से गेंद ले जाते हुए सीधी हिट पर गोल किया। तीन गोल गंवाने के बाद जर्मन टीम ने पलटवार ने 48वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर बनाया लेकिन गोल नहीं कर सकी।

महाराष्ट्र के नागपुर में रक्षाबंधन से पहले छात्रों ने बांस, कागज और पत्तियों से तैयार की 65 गुणा 75 फीट की विशाल 'महाराखी'। स्कूल परिसर में बनाई गई इस अनूठी राखी के साथ नजर आए छात्र।

जी.वी. नारायण राव का निधन

तेलुगु सिनेमा के अभिनेता और निर्माता जी.वी. नारायण राव का 73 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन की पुष्टि अभिनेत्री कराटे कल्याणी ने की। नारायण राव ने 1976 में के. बालचंदर की फिल्म 'अंथुलेनी कथा' से करियर शुरू किया था। करीब पांच दशक के करियर में उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में अभिनय किया। 'ओका ऊरी कथा', 'ऊरुकिचिना माता', 'मंचु पल्लाकी' जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने चिरंजीवी और रजनीकांत जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम किया। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा और 'चेत्तानिकी कल्लू लेवु', 'देवान्थकुडु' और 'यमुदिकी मोगुडु' जैसी फिल्मों का निर्माण किया। टीवी पर भी उन्होंने 'पासुपु कुमकुमा' और 'सुंदरकांडा' जैसे धारावाहिकों में काम किया।

रक्षाबंधन

राखी का बंधन है, बहुत प्यारा और निराला,
भाई-बहन के रिश्ते ने, जीवन को है सँवारा।
ये सिर्फ़ एक धागा नहीं, प्यार की है निशानी,
अपनेपन की खुशबू लेकर, आई है ये कहानी।

बहन की दुआओं में, भाई की मुस्कान रहे,
हर कदम पर दोनों के, दिल में सम्मान रहे।
सुख-दुख में साथ निभाएँ, हाथ कभी न छूटे,
प्यार का ये रिश्ता जीवनभर कभी न टूटे।

राखी के इस पावन दिन, खुशियों के दीप जलाएँ,
भाई-बहन मिलकर आज, प्यार के गीत सुनाएँ।
रक्षा-सूत्र है निभाने का, वादा दिल से प्यारा,
राखी का बंधन है, सबसे सुंदर रिश्ता हमारा।

गोबिंद कुमार विश्वास, मालीगांव, गुवाहाटी

रक्षाबंधन

रक्षाबंधन पर्व है,
सब पर्वों में खास
इसमें भाई का वचन,
बहना का विश्वास
कच्चे धागों में बड़ी,
मजबूती का जोड़
सबसे पावन है यही,
रक्षा का अहसास
है पौराणिक मान्यता,
ईश्वर की है भेंट
है नेमत अल्लाह की,
सतगुरु की अरदास
जिनके हो बहना नहीं,
उनसे पूछो दर्द
शिकवा करती आत्मा,
यूं न होता काश
बेटा-बेटी दोनों ही,
जिस घर लेते जन्म
सारे जग की ही खुशी,
उस घर करती वास
बहना बिन भाई दुखी,
रहता है इस रोज
भाई के बिन बहना भी
रहती सदा उदास

राजगजल 'गजलराज'

ৰাইজৰ কথা ৰাইজৰ মাজলৈ
সাপ্তাহিক
জন জন বিচাৰ
Guwahati, 28 August, 2026 Friday :: শুক্রবাৰ, শাওণ, শুক্ল পক্ষ, পূর্ণিমা, শকাব্দ ১৯৪৮

মেৰাপানীত অসমীয়া লোকক আক্রমণৰ অভিযোগক লৈ উত্তেজনা

জন জন বিচাৰ
...✍ মেৰাপানী

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মেৰাপানীত এজন অসমীয়া লোকক নাগা লোকৰ এটা দলে আক্রমণ কৰাৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ উত্তেজনাই দেখা দিছে। এই ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।

প্রতিবাদকাৰীসকলে কিছু সময়ৰ বাবে পথ অৱৰোধ কৰি ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায়। লগতে স্পর্শকাতৰ সীমান্ত অঞ্চলটোত বসবাস কৰা লোকসকলৰ নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে।

প্রতিবাদৰ মাজতে অসমীয়া আৰু নাগা লোকৰ মাজত বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হোৱাত পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী, বন বিভাগৰ বিষয়া আৰু জ্যেষ্ঠ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্রণলৈ আনে।

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নিৰাপত্তা কটকটীয়া

ইফালে, অসমীয়া বাসিন্দাসকলে নংচ নেঘেৰিবিলত নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া টহলক লৈও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁলোকৰ দাবী, উক্ত অঞ্চলটো অসমৰ ভুখণ্ডৰ অন্তৰ্গত।

সীমান্ত নিৰপেক্ষ নিৰাপত্তা বাহিনী হিচাপে মোতায়েন কৰা চিআৰপিএফৰ ভূমিকাক লৈও একাংশ বাসিন্দাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেওঁলোকৰ অভিযোগ, পূৰ্বেও বিভিন্ন বিবাদৰ সময়ত বাহিনীটোৰ একাংশ জোৱানে নাগা পক্ষৰ প্ৰতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ কৰিছিল। অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই।

উল্লেখ্য, অসম-নাগালেণ্ড সীমা বিবাদক লৈ অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্তেজনা অব্যাহত আছে। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি, যোৱা বছৰৰ আগষ্টত অসম বন বিভাগে অঞ্চলটোত অবৈধ বেদখল উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পিছতো নংচ নেঘেৰিবিল দখলৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে।

পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰি পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে। আক্ৰমণৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থাৰ তথ্য এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ পোৱা নাই।

প্ৰৱঞ্চনা: দিল্লীৰ পৰা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ সোণাৰি আৰক্ষীৰ

সোণাৰি: পানী বিশুদ্ধকৰণ প্ৰকল্প স্থাপনৰ নামত ১২ লাখ টকাৰ অগ্ৰিম ধন লৈ প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত সোণাৰি আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ পৰা এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজনক বিজয় দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। দিল্লী আৰক্ষীৰ সহযোগত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা দিল্লীৰ মংগলপুৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা তেওঁক আটক কৰা হয়।

অভিযোগ অনুসৰি, সোণাৰিৰ বাসিন্দা ভৱান ফুকনে ২০২১ চনত পানী বিশুদ্ধকৰণ প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে বিজয় দাসক ১২ লাখ টকা অগ্ৰিম হিচাপে দিছিল। কিন্তু ধন লাভ কৰাৰ পিছতো প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি প্ৰকল্পটো স্থাপন কৰা নহ'ল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।

আৰক্ষীৰ মতে, ধন লোৱাৰ পিছতে অভিযুক্তজনে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি পলায়ন কৰে। ইয়াৰ পিছতে সোণাৰি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হয়।

তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তজনৰ অৱস্থান দিল্লীত নিশ্চিত কৰে। সোণাৰি আৰক্ষীৰ এটা দলে দিল্লীলৈ গৈ স্থানীয় আৰক্ষীৰ সহযোগত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

নাগা সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ

ইম্ফল: মণিপুৰৰ কাংপোকপি জিলাত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা নাগা সম্প্ৰদায়ৰ সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি সশস্ত্ৰ দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। আক্ৰমণটোত কমেও ৪ জন লোক নিহত, এজন আহত আৰু আন এজন সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে।

জানিব পৰা মতে, পুৱা প্ৰায় ৮.৩০ বজাত আইটি ৰোডৰ মাকুই আশাং আৰু থানাম্বা নাগাৰ মাজৰ অঞ্চলত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয়। এই পথটো আইটি ৰোডৰ কাষত বসবাস কৰা নাগা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যাতায়াত পথ হিচাপে পৰিচিত।

সূত্ৰ অনুসৰি, সশস্ত্ৰ আক্ৰমণকাৰীয়ে পথত নাগা নাগৰিকসকলক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলায়। ঘটনাটোত নাগা সম্প্ৰদায়ৰ কমেও চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এজন লোক আহত হৈছে। আনহাতে, এজন লোকৰ কোনো সন্ধান পোৱা হোৱা নাই।

'বিজেপিত যোগদানৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই'

হিমন্তৰ বিৰুদ্ধে 'মিছা ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ'ৰ অভিযোগ দেবব্ৰত শইকীয়াৰ

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা অসমৰ প্ৰাক্তন বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ জল্পনা-কল্পনা সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিছে। তেওঁ অভিযোগ কৰে যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁক লৈ এনে উৰাবাতৰি ইচ্ছাকৃতভাৱে প্ৰচাৰ কৰি জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে।

শইকীয়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে 'মিছা ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ' চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। তেওঁৰ দাবী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থনত থকা সামাজিক মাধ্যমৰ একাংশ নেটৱৰ্ক আৰু প্ৰচাৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ বিজেপিত যোগদানৰ উৰাবাতৰি বাৰে বাৰে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে।

কংগ্ৰেছ নেতা গৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক ধাৰা আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱালৈকে তেওঁ দলটোত যোগদান কৰাৰ কথা চিন্তাই নকৰে বুলিও কয়।

শইকীয়াই লগতে কয় যে ২০১৬ চনৰ পৰা তেওঁ বিধানসভাৰ পৰা আদালতলৈ অসমৰ জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ, সমস্যা আৰু ন্যায়ৰ বাবে নিৰন্তৰ যুঁজ দি আহিছে। ৰাজনৈতিক উৰাবাতৰি বা হেঁচাই তেওঁৰ স্থিতি সলনি কৰিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ 'অপশাসন'ৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি ঘোষণা কৰে।

সোমনাথ মন্দিৰ দৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুজৰাটৰ প্ৰসিদ্ধ সোমনাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি বাবা সোমনাথৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে।

মন্দিৰ দৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্মৰণ কৰে যে, অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও তেওঁ সোমনাথ মন্দিৰলৈ আহি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল। তাৰ পিছতে নিৰ্বাচনত দলটোৱে বিজয় লাভ কৰিছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে।

এইবাৰ পুনৰ বাবা সোমনাথৰ চৰণত প্ৰণাম জনাবলৈ সোমনাথ মন্দিৰলৈ অহা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়। সোমনাথ মন্দিৰ চৌহদৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে চলি থকা প্ৰচেষ্টাকো তেওঁ আদৰণি জনায়।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, সোমনাথ মন্দিৰৰ ব্যাপক উন্নয়নৰ বাবে এক বৃহৎ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত সোমনাথ কেৱল দেশৰ এক অন্যতম প্ৰধান তীৰ্থস্থান হিচাপেই নহয়, বিশ্ববিখ্যাত তীৰ্থস্থান হিচাপেও গঢ় লৈ উঠিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে।

১৫ দিনৰ ভিতৰতে ছয়দপুৰত উদ্ধাৰ দ্বিতীয়টো মৃতদেহ: নিৰু ৰায়ৰ মৃত্যুক লৈ আতংক

জন জন বিচাৰ
...✍ শিলচৰ

কাছাৰ জিলাৰ ছয়দপুৰ অঞ্চলত মাত্ৰ ১৫ দিনৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়টো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত উদ্বেগ আৰু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মৃত ব্যক্তিজনক প্ৰায় ৪০ বছৰীয়া নিৰু ৰায় বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে।

জানিব পৰা মতে, ২৬ আগষ্টৰ সন্ধিয়া এখন গাঁৱত অনুষ্ঠিত কীৰ্তন অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ পিছত নিৰু ৰায় ঘৰলৈ উভতি অহা নাছিল। পৰিয়ালৰ লোকে নিশাটো বিভিন্ন স্থানত বিচাৰ-খোচাৰ কৰিও তেওঁৰ সন্ধান লাভ কৰা নাছিল।

পিছদিনা পুৱা ছয়দপুৰ বাইপাছৰ সমীপৰ ফকিৰটিলা ৰোডৰ কাষৰ এটা নলাত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। মৃতদেহটোত ধাৰাল অস্ত্ৰৰ আঘাতৰ চিন থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে।

খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰে। পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাটোৰ নিৰপেক্ষ আৰু গভীৰ তদন্ত কৰি দোষীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে।

ইফালে, সোনাবৰিঘাট গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সুমন ৰায়ে অঞ্চলটোত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। একেটা অঞ্চলতে ১৫ দিনৰ ভিতৰত দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ ৰায়পাৰা অঞ্চলত স্থায়ী আৰক্ষী টহল চকী স্থাপনৰ দাবী জনায়।

আৰক্ষীৰ তদন্ত আগবঢ়াৰ লগে লগেহে নিৰু ৰায়ৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ আৰু ঘটনাটোত কোনো লোক জড়িত আছে নে নাই, সেয়া স্পষ্ট হ'ব।

নগাঁওত ওভাৰটেকক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘৰ্ষ যুৱকক ধাৰালো অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ

জন জন বিচাৰ
...✍ নগাঁও

নগাঁও চহৰৰ নিউ মাৰ্কেট এলেকাত বৃহস্পতিবাৰে এখন বাইক আৰু স্কুটাৰ ওভাৰটেক কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা বাক-বিতণ্ডাই সংঘৰ্ষৰ ৰূপ লয়। অভিযোগ অনুসৰি, এদল যুৱকে এজন যুৱকক ধাৰালো অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে। ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় বাইজে অস্ত্ৰটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অভিযুক্ত যুৱককেইজনক আটক কৰি কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত গতাই দিয়ে। আটক যুৱককেইজনৰ নাম প্ৰবীণ বৰা, আদিত্য দাস আৰু বিদ্যুৎ বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে।

ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নিউ মাৰ্কেট এলেকাত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয়। আৰক্ষীৰ পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অধিক তথ্যৰ অপেক্ষা কৰা হৈছে।

ৰক্ষা বন্ধনত মৰম, সম্প্ৰীতি আৰু নাৰীৰ প্ৰতি সন্মানৰ আহ্বান অৰুণাচলৰ ৰাজ্যপাল কে টি পৰনাইকৰ

ইটানগৰ: ৰক্ষা বন্ধনৰ প্ৰাকক্ষণত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল কে টি পৰনাইকে ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জনাই উৎসৱটোৱে কেৱল ভাতৃ-ভগ্নীৰ সম্পৰ্ক উদযাপন কৰাই নহয়, মৰম, সহমৰ্মিতা, সম্প্ৰীতি, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰো বাৰ্তা বহন কৰে বুলি মন্তব্য কৰে।

ইটানগৰৰ লোক ভৱনত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কয় যে হাতত বন্ধা ৰাখী হৈছে প্ৰয়োজনৰ সময়ত ইজনে সিজনৰ কাষত থকাৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি। এই মূল্যবোধৰ জৰিয়তে এখন অধিক মানবীয় আৰু সমন্বিত সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰি বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। অনুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকলে ৰাজ্যপালৰ হাতত ৰাখী বান্ধে। পৰনাইকে শিক্ষাৰ্থীসকলক নিজৰ পছন্দৰ বিষয়ত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জনৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আৰু আকাংক্ষা পূৰণত সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে। ব্ৰহ্মকুমাৰী সংগঠনৰ সদস্যসকলেও ৰাজ্যপালক ৰাখী বান্ধে। সংগঠনটোৰ নিঃস্বাৰ্থ সেৱা, নৈতিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, শান্তি আৰু সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ বাবে চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰো তেওঁ প্ৰশংসা কৰে।

জোৰাবাটত ভয়ংকৰ জলাবদ্ধতা, ৬-৭ ফুট পানীত বুৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত শুকুৰবাৰে পুৱাই জোৰাবাট অঞ্চলত ভয়ংকৰ জলাবদ্ধতাৰ সৃষ্টি হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেইবাটাও অংশত পানীৰ স্তৰ ছৰ পৰা ৭ ফুট পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পোৱাত যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২৭ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-৭-ৰ বৃহৎ অংশ পানীৰ তলত বুৰ যোৱাত গুৱাহাটী আৰু শ্বিলঙৰ মাজত চলাচল কৰা বহু যান-বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে।

পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰাৰ পিছত ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। উদ্ধাৰকাৰীসকলে নাওৰ সহায়ত জলমগ্ন অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়।

ইফালে, বানপানীৰ মাজত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কঢ়িওৱা এখন বাছ আবদ্ধ হৈ পৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয়। আনহাতে, সামগ্ৰী কঢ়িওৱা এখন বৃহৎ বাহন ঘাইপথৰ মাজতে বিকল হৈ পৰাত যান-বাহনৰ চলাচলত অধিক বাধাৰ সৃষ্টি হয়।

জোৰাবাটৰ লগতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো ব্যাপক জলাবদ্ধতা দেখা দিয়ে। পথসমূহত পানী জমা হোৱাৰ ফলত সাধাৰণ যাত্ৰী, কৰ্মস্থলীলৈ যোৱা লোক আৰু বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়।

জোৰাবাটত চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰত এইবাৰৰ জলাবদ্ধতাক এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অতি প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ এই পথেৰে যাত্ৰা নকৰিবলৈ যাত্ৰীসকলক সতৰ্ক কৰা হৈছে। গুৱাহাটী, শ্বিলং আৰু উজনি অসমৰ মাজত চলাচল কৰা অসংখ্য যান-বাহন আবদ্ধ হৈ পৰাত দীঘলীয়া যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে।

এই সপ্তাহৰ ৰাশিফল

~~২১ আগষ্ট, ২০২৬ৰ পৰা ২৭ আগষ্ট, ২০২৬লৈ~~

মেষ : মানসিকতা অস্থিৰতা বৃদ্ধি। ধৰ্মীয় কাৰ্ঞ্জয্যত মনোনিবেশ থাকিব। বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে সপ্তাহটো শুভ।

বৃষ: কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি হব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। চেষ্টাৰ সফলতা লাভ।

মিথুন: খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত বাদ বিবাদৰ পৰা আতৰি থাকক। আত্মীয় স্বজনৰ পৰা লাভ।

কৰ্কট: মানসিক অস্থিৰতা থাকিব। ধৰ্মীয় কাৰ্ঞ্জয্যত মনোনিবেশ থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন।

সিংহ: আকস্মিক হব পৰা অনাকাংক্ষিত ব্যায়ৰ পৰা সতৰ্ক হব। অদৰকাৰী বাদ বিবাদৰ পৰা আতৰি থাকক। বিদ্যাৰ্থীৰ শুভ।

কন্যা : ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ। আদৰকৰি কথাত কাৰ্ঞ্জয্যদক্ষতা প্ৰদৰ্শনৰ পৰা বিৰত থাকক। আকস্মিক লাভৰ সম্ভাৱনা আছে।

তুলা: কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মদক্ষতাৰ সুনাম অৰ্জন। ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ।

বৃশ্চিক: মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি। প্ৰতিযগিতামূলক কাৰ্ঞ্জয্যত সফলতা অৰ্জন। ভ্ৰমণৰ পৰা আনন্দ লাভ।

ধনু : আদৰকাৰী কাৰ্ঞ্জয্যত সময় অপচয় । মাতৃৰ শাৰীৰ স্বাস্থৰ প্ৰতি সচেতন হব। দুশ্চিন্তাই মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে।

মকৰ: অস্বাস্থ্যজনক ভোজনৰ প্ৰতি সচেতন হব। ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ পৰা লাভ। মানসিক সুস্থিৰতা বৃদ্ধি।

কুম্ভ : দৈনন্দিন কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো শুভ। চেষ্টাৰ সফলতা লাভ।

মীন: মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি। সন্তানৰ কৃতকাৰ্ঞ্জয্যতাৰ পৰা গৌৰৱ অৰ্জন। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো শুভ।

-হিতেন শৰ্মা শাস্ত্ৰী
অধ্যাপক, বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠ, অসম শাখা
যোগাযোগ : ৯৮৫৪০২৬৭৭৯

ধিঙত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গৌৰৱ গগৈৰ 'ভোট চুৰি'ৰ অভিযোগ, বান সাহায্য বিতৰণতো পক্ষপাতিত্বৰ দাবী

জন জন বিচাৰ
...✍ ধিং

আগন্তুক ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ ৰাজনীতিত পুনৰ বাক-বিতণ্ডা তীব্ৰ হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে 'ভোট চুৰি' ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগতে ধিং অঞ্চলত বান সাহায্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰতো দলীয় পক্ষপাতিত্ব কৰা বুলি দাবী কৰিছে।

২৭ আগষ্টত ধিং আৰু নিজ-ধিং খণ্ড কংগ্ৰেছ সমিতিয়ে আয়োজন কৰা বুথ পৰ্যায়ৰ কৰ্মী সন্মিলনত ভাষণ দি গৌৰৱ গগৈয়ে অভিযোগ কৰে যে বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ১৫ হাজাৰ টকাৰ সাহায্য সকলো উপযুক্ত লোকৰ মাজত সমানে বিতৰণ কৰা হোৱা নাই। তেওঁৰ দাবী অনুসৰি, বিজেপিৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে সাহায্য লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ তথা আন ৰাজনৈতিক দলৰ সমৰ্থক বুলি পৰিচিত লোকসকলক এই সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে।

গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত বানাক্ৰান্ত লোকৰ ৰাজনৈতিক পৰিচয় বিচাৰি সাহায্য বিতৰণ কৰাটো অমানবীয় আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ পৰিপন্থী। অৱশ্যে, এই অভিযোগৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰমাণ বা চৰকাৰৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ সময়লৈকে পোহৰলৈ অহা নাই।

'ভোট চুৰি'ক লৈ বিজেপিক আক্ৰমণ

উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী অনিয়মৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে। তেওঁ শাসকীয় দলটোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত 'ভোট চুৰি' কৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ কৰে। তেওঁৰ বক্তব্যৰ মূল লক্ষ্য আছিল আগন্তুক উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰা আৰু বুথ পৰ্যায়ত দলীয় কৰ্মীসকলক সক্ৰিয় কৰা।

ধিঙৰ উপ-নিৰ্বাচনক ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজনৈতিক মহলত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। সেয়েহে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসক আৰু বিৰোধী দুয়ো পক্ষৰ মাজত অভিযোগ-প্ৰতিআৰোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।

সম্ভাব্য বিজেপি প্ৰাৰ্থীক লৈও চৰ্চা

ইফালে নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে বুলি প্ৰকাশ পোৱা খবৰক লৈও গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰে। অৱশ্যে বিজেপিয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই।

আনহাতে, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছক সহায় কৰাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলি ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি (মাক্সবাদী-লেনিনবাদী)ৰ নেতা অখিল গগৈয়ে কৰা বুলি প্ৰকাশিত মন্তব্যক লৈও কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। গৌৰৱ গগৈৰ লগতে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনেও এই বিষয়ত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰে।

প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কংগ্ৰেছতো আশা

প্ৰাক্তন বিধায়ক শিৰামণি বৰাই ধিং উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশ্যে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, সেই সিদ্ধান্ত মানি ল'ব বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰে।

ধিঙত অনুষ্ঠিত বুথ পৰ্যায়ৰ এই সন্মিলনত গৌৰৱ গগৈৰ উপৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইন, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ চৌহান, বিধায়ক নুৰুল হুদা, তাঞ্জিল হুছেইন আৰু নুৰুল ইছলাম, মীৰা বৰঠাকুৰকে ধৰি বহু নেতা আৰু দলীয় কৰ্মী উপস্থিত থাকে।

উপ-নিৰ্বাচনৰ দিন ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে ধিঙত ৰাজনৈতিক তৎপৰতা অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বান সাহায্যৰ বিতৰণ, সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু নিৰ্বাচনী স্বচ্ছতাক লৈ উঠা অভিযোগসমূহে আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ অধিক উত্তপ্ত কৰি তুলিব পাৰে।

কলিয়াবৰৰ শালবাৰী বিদ্যালয়ত ৫৫ শিক্ষাৰ্থীৰ ভাৰ এজন শিক্ষকৰ

জন জন বিচাৰ
...✍ কলিয়াবৰ

শিক্ষকৰ অভাৱ আৰু সীমিত আন্তঃগাঁথনিৰ মাজতো প্ৰায় ৪০ বছৰ ধৰি শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাই আহিছে কলিয়াবৰৰ শালবাৰী ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে। কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক দায়িত্ব এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে এজন শিক্ষকৰ কান্ধত।

বিদ্যালয়খনৰ একমাত্ৰ শিক্ষক ৰাম সিং ৰামচিয়াৰীয়ে ৫৫গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক অকলে পাঠদান কৰি আহিছে। সামান্য দৰমহাত 'টিউটৰ' হিচাপে কৰ্মৰত ৰামচিয়াৰীয়ে শিক্ষক আৰু অন্যান্য মৌলিক সুবিধাৰ অভাৱৰ মাজতো নিয়মীয়াকৈ পাঠদান অব্যাহত ৰাখিছে।

প্ৰায় চাৰি দশক পূৰ্বে স্থাপিত বিদ্যালয়খনে এতিয়াও প্ৰাদেশিকীকৰণৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা নাই। ফলত পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তি নোহোৱাৰ বাবে এজন শিক্ষকৰ ওপৰতে বিপুল দায়িত্ব পৰিছে।

শিক্ষকৰ অভাৱত যাতে শিক্ষাৰ্থীৰ পাঠদান ব্যাহত নহয়, তাৰ বাবে ৰামচিয়াৰীয়ে ডিজিটেল শিক্ষণ পদ্ধতিৰ সহায় লৈছে। সীমিত সম্পদৰ মাজতো প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠৰ সৈতে জড়িত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে তেওঁ।

তেওঁৰ এই নিষ্ঠাক স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশংসা কৰিছে। বিদ্যালয়খনৰ পৰিস্থিতিয়ে অসমৰ বহু শিক্ষানুষ্ঠানত পৰ্যাপ্ত শিক্ষক আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও পুনৰ উন্মোচন কৰিছে।

এজন শিক্ষক, ৫৫জন শিক্ষাৰ্থী-শালবাৰী বিদ্যালয়ৰ এই ছবিখন কেৱল নিষ্ঠাৰ কাহিনী নহয়, শিক্ষাখণ্ডৰ এক গুৰুতৰ বাস্তৱতাও।

বানত বিধ্বস্ত নেপালত আবদ্ধ অসমৰ লোকৰ বাবে জৰুৰী সহায়তা ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰৰ

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী

নেপালৰ কেইবাটাও অঞ্চলত ভয়ংকৰ বানপানীৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ বহু লোক আবদ্ধ হৈ পৰাৰ মাজতে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ নেপালত আবদ্ধ লোকসকলৰ বাবে জৰুৰী সহায়তা আৰু সমন্বয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।

নতুন দিল্লীৰ অসম ভৱনৰ আৱাসিক আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে বানপানীত আবদ্ধ অসমৰ বাসিন্দাসকলক তাৎক্ষণিক সহায় আৰু প্ৰয়োজনীয় সমন্বয়ৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট বিষয়াসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰিছে।

জৰুৰী সহায়তাৰ বাবে এচিএছ অৰুণম মেধিৰ সৈতে ৯১-৯১০৮০৯১৫৯১ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আনহাতে, অসম ভৱনৰ গৃহ পৰিচালক বিনোদ কলিতাৰ সৈতে ৯১-৮৯২০৫৭০৫০৭ নম্বৰত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

ইয়াৰ উপৰি অসম ভৱনে তিনিটা জৰুৰী টেলিফোন নম্বৰ সক্ৰিয় কৰি ৰাখিছে-০১১-২৩০১০২৯৯, ০১১-২৩০১০২৯৮ আৰু ০১১-২৬৮৭১১১১।

অসম চৰকাৰে নেপালৰ বানপীড়িত অঞ্চলত আবদ্ধ অসমৰ নাগৰিকসকলক আতংকিত নহৈ উল্লিখিত যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি তাৎক্ষণিক সহায় আৰু প্ৰশাসনিক সমন্বয় বিচাৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।

ত্ৰিপুৰাত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ প্ৰস্তুতি

আগৰতলা: ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনভোগীসকলৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চনৰ সংশোধনৰ বাবে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ বিত্তমন্ত্ৰী প্ৰণজিৎ সিংহ ৰায়ে ২৭ আগষ্টত বিধানসভাত এই কথা ঘোষণা কৰে।

বিধানসভাৰ অধিৱেশনত হোৱা আলোচনাৰ সময়ত বিধায়ক সুদীপ ৰয় বৰ্মনে বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ লগতে বিৰোধী দলপতি জিতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়েও আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰে। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰস্তাৱিত আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্য পদৰ বাবে সম্ভাব্য ব্যক্তিসকলৰ নাম বৰ্তমান চৰকাৰে পৰ্যালোচনা কৰি আছে। উপযুক্ত ব্যক্তিক দায়িত্ব প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। প্ৰণজিৎ সিংহ ৰায়ে লগতে কয় যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত থকা বৈষম্য আৰু অসামস্যৰ বিষয়সমূহো প্ৰস্তাৱিত আয়োগৰ বিবেচনাৰ আওতালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আয়োগে এই সমস্যাসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি উপযুক্ত পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে।

সম্পাদকীয়

শ্বিলঙৰ বিকল্প বিচৰাৰ সময়, নে সম্পৰ্কৰ সেতু মজবুত কৰাৰ সময়?

অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাই আন্তঃৰাজ্যিক সম্পৰ্কৰ লগতে পৰ্যটন খণ্ডতো নতুন প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উমৰাংছ', হাফলং আৰু ডিফুক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত শ্বিলঙৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পৰা গন্তব্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কথা কৈছে। প্ৰস্তাৱটো সময়োপযোগী, কিন্তু ইয়াক কেৱল মেঘালয়ৰ বিৰুদ্ধে বিকল্প সৃষ্টি কৰাৰ মানসিকতাৰে আগবঢ়োৱা উচিত নহয়।

উমৰাংছ', হাফলং আৰু ডিফু অসমৰ অমূল্য প্ৰাকৃতিক সম্পদ। পাহাৰ, জলাশয়, বনাঞ্চল, মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিয়ে এই অঞ্চলসমূহক পৰ্যটনৰ বাবে অপাৰ সম্ভাৱনাময় কৰি তুলিছে। উন্নত পথ-যোগাযোগ, বিমান সেৱা, নিৰাপদ পৰিৱেশ, মানসম্পন্ন হোটেল আৰু পৰ্যটকসেৱা, স্থানীয় খাদ্য-সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু দক্ষ পৰ্যটন পৰিচালনাৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলসমূহক দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ কৰি তুলিব পাৰি। ইয়াৰ ফলত স্থানীয় যুৱ সমাজৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপন আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰো দুৱাৰ মুকলি হ'ব।

কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল-অসমে নিজৰ পৰ্যটন শক্তি গঢ়িব নে শেহতীয়া উত্তেজনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত কেৱল "শ্বিলঙৰ বিকল্প" বিচাৰিব? দ্বিতীয় পথটো কোনোপধ্যে সুদূৰপ্ৰসাৰী নহয়। মেঘালয় অসমৰ শত্ৰু নহয়; দুয়োখন ৰাজ্যৰ মানুহৰ মাজত বহু পুৰণি সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আছে।

সেয়ে চৰকাৰে পৰ্যটন উন্নয়নক প্ৰতিযোগিতাৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰাই দীৰ্ঘম্যাদী অৰ্থনৈতিক নীতি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। একে সময়তে অসম-মেঘালয়ৰ মাজৰ উত্তেজনা হ্ৰাস কৰি নিৰাপদ যাতায়াত আৰু পাৰস্পৰিক বিশ্বাস পুনৰ স্থাপন কৰাটোও জৰুৰী। অসমে শ্বিলঙক হৰুৱাবলৈ নহয়, নিজৰ উমৰাংছ', হাফলং আৰু ডিফুক বিশ্বৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আগবাঢ়ক। এয়াই হ'ব অসমৰ বাবে অধিক শক্তিশালী আৰু সন্মানজনক পথ।

মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত সৰ্বসাধাৰণ: চৰকাৰ জনতাৰ পক্ষত নে ব্যৱসায়িক অভিজাতৰ?

জন জন বিচাৰ

...✍ সুজল প্ৰধান

ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন-যাপন ক্ৰমাৎ কঠিন কৰি তুলিছে। খাদ্যসামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঔষধ, ৰন্ধন তেল, চেনি, পিঁয়াজ আদি দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাত পৰিয়ালসমূহৰ মাহেকীয়া বাজেটত ব্যাপক চাপ পৰিছে। এনে সময়তে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা (আছু)ই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে।

গুৱাহাটীৰ উজানবজাৰৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ সমীপত আছুৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰে। আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই মূল্যবৃদ্ধিৰ সৈতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে।

তেওঁৰ বক্তব্যত এটা প্ৰশ্ন বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ-"নিৰ্বাচনৰ সময়ত সামগ্ৰীৰ দাম তুলনামূলকভাৱে স্থিৰ থাকে, কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতেই দাম হঠাৎ বাঢ়িবলৈ ধৰে কিয়?" এই প্ৰশ্ন কেৱল আছুৰ নহয়; বজাৰত প্ৰতিদিনে সামগ্ৰী কিনিবলৈ বাধ্য হোৱা সাধাৰণ গ্ৰাহকৰো একেই প্ৰশ্ন।

শেহতীয়াকৈ অসমৰ তিনিখন জিলাত বানপানীয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছে। বহু পৰিয়ালে ঘৰ-বাৰী, কৃষিভূমি আৰু জীৱিকাৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। এনে এক দুৰ্যোগৰ সময়ত বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যদি অধিক বৃদ্ধি পায়, তেন্তে বানপীড়িত আৰু নিম্নআয়ৰ পৰিয়ালসমূহৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিমান ভয়াবহ হ'ব পাৰে, সেয়া সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি।

আছুৰ অভিযোগ, বানপানীক মূল্যবৃদ্ধিৰ অজুহাত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি কোনো কোনো অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কৃত্ৰিমভাৱে সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। যদি এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তেন্তে প্ৰশাসনে কেৱল অভিযোগ শুনি থকাই নহয়, বজাৰত অভিযান চলাই দায়ী ব্যৱসায়ীসকলক চিনাক্ত কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।

কাৰণ বানপানী বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে যোগান ব্যৱস্থাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, কিন্তু প্ৰতিটো মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা গ্ৰাহকৰ ওপৰত জাপি দিয়াটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়।

মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটতো আছুৰ প্ৰতিবাদে ব্যাপক ৰূপ লয়। যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ পৰা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায়। শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চৰকাৰ আৰু যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণত অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায়।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম শীঘ্ৰে হ্ৰাস কৰা, বজাৰ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা আৰু কৃত্ৰিমভাৱে দাম বৃদ্ধি কৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায়।

আছুৰ তথ্য অনুসৰি, যোৱা প্ৰায় ৰপ্ত দিনত পিঁয়াজৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত প্ৰায় ১৬ টকা বৃদ্ধি পাইছে। চেনিৰ দামো প্ৰতি কিলোগ্ৰামত প্ৰায় ৰপ্তৰ পৰা ২০ টকালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। সৰিয়হ তেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত প্ৰায় ৮ টকা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতো সাধাৰণ পৰিয়ালসমূহৰ ওপৰত অতিৰিক্ত আৰ্থিক বোজা পৰিছে।

এইবোৰ সংখ্যা হয়তো কাগজত সৰু যেন লাগিব পাৰে। কিন্তু সীমিত উপাৰ্জনৰ এটা পৰিয়ালৰ বাবে মাহৰ শেষত প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি একেলগ হৈ বৃহৎ আৰ্থিক সংকটৰ সৃষ্টি কৰে।

মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সাধাৰণতে যোগান-চাহিদাৰ ভাৰসাম্য, পৰিবহণ ব্যয়, উৎপাদন ব্যয়, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদি কাৰণৰ কথা উল্লেখ কৰে। এই কাৰণবোৰ বাস্তৱ আৰু বহু ক্ষেত্ৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত। কিন্তু ইয়াৰ মাজত যদি কোনো অসাধু চক্ৰই মজুতদাৰী, কৃত্ৰিম নাটনি অথবা অতিৰিক্ত লাভৰ উদ্দেশ্যে সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰে, তেন্তে সেই বিষয়টোও কঠোৰভাৱে পৰীক্ষা কৰা প্ৰয়োজন।

চৰকাৰৰ দায়িত্ব কেৱল সামগ্ৰীৰ যোগান নিশ্চিত কৰাতেই সীমাবদ্ধ নহয়। সাধাৰণ গ্ৰাহকে যাতে ন্যায্য মূল্যত সামগ্ৰী লাভ কৰে, সেয়াও এখন কল্যাণকামী চৰকাৰৰ মৌলিক দায়িত্ব।

বজাৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ নিয়মীয়া অভিযান, মূল্য তালিকা পৰীক্ষা, মজুতৰ তথ্য সংগ্ৰহ আৰু কৃত্ৰিম মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন আছে। কেৱল প্ৰতিবাদৰ পাছত অভিযান চলাই পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি গকলে সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নহয়।

আছুৰ প্ৰতিবাদে এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে-চৰকাৰ জনতাৰ পক্ষত নে কেৱল বজাৰৰ শক্তিশালী অংশটোৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাত ব্যস্ত?

এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চৰকাৰেই দিব লাগিব। মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা যেতিয়া মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত আৰু দৈনিক উপাৰ্জনকাৰী লোকৰ ওপৰত পৰে, তেতিয়া কেৱল মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিলেই চৰকাৰৰ দায়িত্ব শেষ নহয়। কাৰণ বিচাৰি উলিওৱা, দোষীক শাস্তি দিয়া আৰু গ্ৰাহকক সকাহ দিয়াটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ।

আছুৱে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য উল্লেখযোগ্যভাৱে হ্ৰাস নোহোৱালৈকে তেওঁলোকৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। সেয়েহে চৰকাৰৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ কেৱল এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ আন্দোলন হিচাপে দেখাটো ভুল হ'ব। ই জনসাধাৰণৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে জড়িত এক মৌলিক সমস্যা।

মূল্যবৃদ্ধি যদি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যায়, তেন্তে উন্নয়নৰ সকলো পৰিসংখ্যাই সাধাৰণ মানুহৰ পাকঘৰত অৰ্থহীন হৈ পৰে। চৰকাৰৰ প্ৰকৃত সফলতা তেতিয়াহে প্ৰতিফলিত হ'ব, যেতিয়া এজন সাধাৰণ মানুহে বজাৰলৈ গৈ নিজৰ সীমিত উপাৰ্জনৰ ভিতৰতে পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কিনিব পাৰিব।

এতিয়া সময় হৈছে চৰকাৰে প্ৰতিবাদৰ ভাষা শুনি বজাৰৰ বাস্তৱ ছবিখন পৰীক্ষা কৰাৰ। জনতাৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা জাপি দি কোনো ৰাজ্যই স্থায়ী উন্নয়নৰ দাবী কৰিব নোৱাৰে।

উত্তৰ প্ৰদেশ : সমীক্ষাত অখিলেশ আগত যোগীৰ সন্মুখত জাতিগত সমীকৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান

জন জন বিচাৰ
...✍ লখনউ

উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰৱৰ্তী বিধানসভা নিৰ্বাচন এতিয়াও কিছু দূৰৈত যদিও ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক ময়দানত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ উত্তাপ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। শেহতীয়া 'ষ্টেট ভাইব ছাৰ্ভে'ত শাসক পক্ষ আৰু বিৰোধীৰ মাজত অতি সামান্য ব্যবধানৰ ইংগিত পোৱা গৈছে। সমীক্ষা অনুসৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএক ৪১.১ শতাংশ লোকৰ সমৰ্থনৰ বিপৰীতে অখিলেশ যাদৱৰ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক ৪১.২ শতাংশ সমৰ্থন জনোৱা হৈছে। মাত্ৰ ০.১ শতাংশৰ ব্যৱধানে নিৰ্বাচনী যুঁজখন কিমান ওচৰা-ওচৰি হ'ব পাৰে তাৰ ইংগিত দিছে।

অৱশ্যে কোনো সমীক্ষাক নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত ফলাফল হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি। নিৰ্বাচনলৈ সময় আছে আৰু ভোটাৰৰ মনোভাৱ প্ৰাৰ্থী, মিত্ৰজোঁট, স্থানীয় সমস্যা, চৰকাৰৰ কাম-কাজ আৰু নিৰ্বাচনী পৰিৱেশৰ সৈতে সলনি হ'ব পাৰে। তথাপিও এই পৰিসংখ্যাই উত্তৰ প্ৰদেশত বাঢ়ি অহা ৰাজনৈতিক প্ৰতিযোগিতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবি দাঙি ধৰিছে।

যোগী বনাম অখিলেশ: মুখৰ যুঁজৰ পৰা আগবাঢ়ি সামাজিক সমীকৰণলৈ

উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনৈতিক যুঁজ এতিয়া কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ আৰু সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱৰ জনপ্ৰিয়তাত সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। সামাজিক সমীকৰণ, সংৰক্ষণ, সংবিধান, সংস্থাপন, আইন-শৃংখলা আৰু উন্নয়নৰ দৰে বিষয়েও নিৰ্বাচনী আলোচনাৰ কেন্দ্ৰলৈ আহিছে।

যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে শাসন, আইন-শৃংখলা আৰু উন্নয়নৰ অভিলেখক নিৰ্বাচনী বিষয় হিচাপে আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব। আনহাতে অখিলেশ যাদৱে সামাজিক ন্যায়, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ অংশীদাৰিত্ব, জাতিগত জনগণনা আৰু সংৰক্ষণৰ দৰে বিষয়ক অধিক গুৰুত্ব দি বিৰোধী শিবিৰক একত্ৰিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে।

বিজেপিৰ সন্মুখত ডাঙৰ প্ৰশ্ন-'সামাজিক সন্তুলন'

বিজেপিৰ শক্তিশালী দিশ হৈছে ইয়াৰ বিস্তৃত সামাজিক সংগঠন। সাধাৰণ ভোটাৰৰ লগতে পিছপৰা আৰু অতি-পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন গোটৰ মাজতো দলটোৱে বিগত বছৰসমূহত নিজৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিছে।

কিন্তু ২০২৭ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বাবে দুটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান থাকিব-পৰম্পৰাগত উচ্চবৰ্ণৰ সমৰ্থন অটুট ৰখা আৰু পিছপৰা, অতি-পিছপৰা তথা দলিত ভোটাৰৰ মাজত নিজৰ প্ৰভাৱ বজাই ৰখা।

২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশত সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে ৩৭খন আৰু কংগ্ৰেছে ৬খন আসন লাভ কৰিছিল। সংবিধান আৰু সংৰক্ষণৰ বিষয়ক বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্যতম কেন্দ্ৰীয় বিষয় কৰি তুলিছিল। এতিয়া ২০২৭ৰ পূৰ্বে সেই বিষয়সমূহ পুনৰ ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰলৈ অহা দেখা গৈছে।

অখিলেশৰ সন্মুখতো সহজ পথ নাই

সমীক্ষাত সামান্য আগবাঢ়ি থকাটো অখিলেশ যাদৱৰ বাবে উৎসাহজনক সংকেত হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াক জয়ৰ নিশ্চয়তা বুলি ধৰা বিপজ্জনক। সমাজবাদী পাৰ্টিৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নিজৰ সামাজিক মিত্ৰজোঁটক ভোটলৈ ৰূপান্তৰ কৰা।

পিছপৰা আৰু সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ওপৰত দলটোৰ পৰম্পৰাগত নিৰ্ভৰতা আছে। কিন্তু বিজেপিৰ বিস্তৃত সাংগঠনিক নেটৱৰ্কক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ অখিলেশে যাদৱ সম্প্ৰদায়ৰ বাহিৰৰ পিছপৰা শ্ৰেণী আৰু বিভিন্ন দলিত গোটৰ মাজতো অধিক সমৰ্থন গঢ়ি তুলিব লাগিব।

মায়াৱতীৰ বিএছপি হ'ব পাৰে 'গেম চেঞ্জাৰ'

এই সমীকৰণত মায়াৱতীৰ বহুজন সমাজ পাৰ্টিৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে। বিএছপি-এ যদি নিজৰ পৰম্পৰাগত দলিত ভোট বেংকৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়, তেন্তে ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ বিজেপি আৰু সমাজবাদী পাৰ্টি-দুয়োৰে নিৰ্বাচনী গণিতত পৰিব পাৰে।

বিশেষকৈ দলিত ভোটৰ সামান্য স্থানান্তৰেও বহু আসনত ফলাফল সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেয়েহে ২০২৭ৰ যুঁজত বিএছপি-এ কিমান ভোট লাভ কৰে, সেইটোও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণায়ক হ'ব পাৰে।

সংৰক্ষণ আৰু জাতিগত জনগণনা-নিৰ্বাচনী অস্ত্ৰ নে বাস্তৱ সমস্যা ?

সংৰক্ষণ আৰু জাতিগত জনগণনাক লৈ চলি থকা ৰাজনৈতিক বিতৰ্কে ২০২৭ৰ নিৰ্বাচনৰ দিশৰ এক স্পষ্ট ইংগিত দিছে। বিৰোধী দলসমূহে সংৰক্ষণ, সামাজিক ন্যায় আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ অধিক অংশীদাৰিত্বৰ দাবী আগবঢ়াইছে। বিজেপিয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ জাতিগত ৰাজনীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিব পাৰে।

কিন্তু এই বিতৰ্কৰ আঁৰত ভোটাৰৰ বাস্তৱ প্ৰশ্নসমূহো আছে-চাকৰি, শিক্ষা, চৰকাৰী চাকৰিত প্ৰতিনিধিত্ব, অৰ্থনৈতিক সুযোগ আৰু ক্ষমতাৰ অংশীদাৰিত্ব।

সেয়ে ২০২৭ৰ নিৰ্বাচনত জাতিগত জনগণনা, সংৰক্ষণ আৰু সংবিধান কেৱল শ্লোগান হৈ নাথাকিব; এইবোৰৰ সৈতে লাখ লাখ যুৱক-যুৱতী আৰু পিছপৰা পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ থাকিব।

০.১ শতাংশৰ ব্যৱধানেই শেষ কথা নহয়

বৰ্তমানৰ সমীক্ষাত অখিলেশৰ শিবিৰে মাত্ৰ ০.১ শতাংশৰ সামান্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে বিশাল ৰাজ্যত এই সৰু ভোট-শ্বেয়াৰৰ পাৰ্থক্যই বহু সমষ্টিত আসনৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব পাৰে।

কোনটো মিত্ৰজোঁটে কিমান আসনত সমন্বয় কৰে, বিএছপি-এ কিমান ভোট কাটি নিয়ে, অ-যাদৱ পিছপৰা আৰু অ-জাটৱ দলিত ভোটাৰৰ মনোভাৱ কি হয়, যুৱ আৰু মহিলা ভোটাৰ কোনটো বিষয়ত একত্ৰিত হয়-এই সকলোবোৰেই চূড়ান্ত ফলাফল নিৰ্ধাৰণ কৰিব।

সেয়ে এতিয়াৰ সমীক্ষাৰ প্ৰকৃত বাৰ্তা অখিলেশ জিকিল বা যোগী হাৰিল নহয়। বাৰ্তা এটাই-উত্তৰ প্ৰদেশৰ ২০২৭ৰ নিৰ্বাচন পুনৰ এক অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি ৰাজনৈতিক যুঁজলৈ আগবাঢ়িছে। এতিয়া সৰু ভোটৰ ব্যৱধানক ডাঙৰ আসনৰ অগ্ৰগতি হিচাপে কোনে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে, সেয়াই হ'ব মূল প্ৰশ্ন।

ভাৰততলৈয়ে হ'ব নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বালেন শ্বাহৰ প্ৰথম বিদেশ ভ্ৰমণ

জন জন বিচাৰ
...✍ কাঠমাণ্ডু

নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বালেন শ্বাহে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰথম বিদেশ ভ্ৰমণ হিচাপে ভাৰতলৈ আহিব পাৰে। নেপালৰ বিত্তমন্ত্ৰী স্বৰ্ণিম ৱাগলেয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। অৱশ্যে ভ্ৰমণৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই। সকলো পৰিকল্পনা অনুসৰি আগবাঢ়িলে চলিত বছৰৰ শেষৰ পূৰ্বেই বালেন শ্বাহে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।

কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত এটা টেলিভিছন অনুষ্ঠানত বক্তব্য ৰাখি বিত্তমন্ত্ৰী ৱাগলেয়ে কয় যে চৰকাৰৰ আৰম্ভণিৰ ১০০ দিন ঘৰুৱা বিষয় আৰু উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত আছিল। এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিদেশ ভ্ৰমণক লৈ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰথম ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ৱাগলেয়ে কয়, "মই সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস কৰোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী বালেন শ্বাহৰ প্ৰথম বিদেশ ভ্ৰমণ ভাৰতলৈয়ে হ'ব।" তেওঁ লগতে জনায় যে ভ্ৰমণৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত এতিয়াও আলোচনা চলি আছে।

১০০ বিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতিৰ লক্ষ্য

অনুষ্ঠানটোত নেপালৰ অৰ্থনৈতিক ১০০ বিলিয়ন ডলাৰলৈ উন্নীত কৰাৰ লক্ষ্য, ভাৰতীয় আৰু নেপালী টকাৰ বিনিময় হাৰ, শেহতীয়া বান সাহায্য আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী বালেন শ্বাহৰ কাৰ্যপদ্ধতিৰ বিষয়েও বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আলোচনা কৰে। ৱাগলেৰ মতে, চৰকাৰৰ প্ৰথম ১০০ দিনৰ কাৰ্যসূচী ১০০টা সূত্ৰৰ এজেণ্ডাৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল। চৰকাৰে এই সময়ছোৱাত নিজৰ কামৰ মূল্যায়নত ৮৭.২ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাংসদ ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে বালেন শ্বাহৰ সম্ভাব্য ভাৰত ভ্ৰমণক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি অভিহিত কৰে। তেওঁ কয় যে ভাৰত আৰু নেপালৰ সম্পৰ্কৰ ভেটি অতি শক্তিশালী আৰু এই সম্পৰ্কক কেৱল সীমান্ত বা পাছপৰ্টৰ সীমাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰিব নোৱাৰি। তেওঁৰ মতে, নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথম বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতক বাছনি কৰাটো দুয়োখন দেশৰ ভৱিষ্যৎ সম্পৰ্ক কোন দিশে আগবাঢ়িব তাৰ এক ইতিবাচক সংকেত।

উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত নেপালৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বালেন শ্বাহৰ নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টিয়ে বৃহৎ জয় লাভ কৰিছিল।

ৰাখীৰ তিনিটা গাঁঠিৰ আঁৰত কি ৰহস্য ? ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু মহেশৰ সৈতে জড়িত এই বিশেষ পৰম্পৰা

কেৰল ভাতৃ-ভগ্নীৰ মৰমৰ প্ৰতীক নহয়, শাস্ত্ৰীয় বিশ্বাসত ৰক্ষাসূত্ৰৰ প্ৰতিটো গাঁঠিৰ আছে বিশেষ তাৎপৰ্য

জন জন বিচাৰ
...বিশেষ প্ৰতিবেদন

ৰক্ষাবন্ধন কেৱল ভাতৃ-ভগ্নীৰ মৰম, বিশ্বাস আৰু সুৰক্ষাৰ পৱিত্ৰ বন্ধনৰ উৎসৱ নহয়; ইয়াৰ সৈতে জড়িত আছে বহু পুৰণি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু বিশ্বাস। এই উৎসৱত ভগ্নীয়ে ভাতৃৰ হাতত ৰক্ষাসূত্ৰ বা ৰাখী বান্ধে আৰু তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য, সুখ-সমৃদ্ধি আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে।

কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে-ৰাখী বান্ধোতে সাধাৰণতে তিনিটা গাঁঠি কিয় দিয়া হয়? এই তিনিটা গাঁঠিৰ সৈতে হিন্দু ধৰ্মৰ ত্ৰিদেৱ-ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে বুলি ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত বিশ্বাস কৰা হয়।

তিনিটা গাঁঠি, তিনিটা বিশেষ অৰ্থ

ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি ৰাখীৰ প্ৰথম গাঁঠিটো ব্ৰহ্মাৰ প্ৰতীক। এই গাঁঠি ভাতৃৰ দীৰ্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য আৰু জীৱনত মংগল কামনাৰে বান্ধা হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।

দ্বিতীয় গাঁঠিটো ভগৱান বিষ্ণুৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয়। এই গাঁঠিৰ সৈতে ভাতৃৰ জীৱনত সুখ, সমৃদ্ধি, নিৰাপত্তা আৰু স্থায়িত্বৰ কামনা জড়িত।

তৃতীয় গাঁঠিটো ভগৱান শিৱ বা মহেশ্বৰ প্ৰতীক বুলি ধৰা হয়। এই গাঁঠিৰ সৈতে মানসিক শান্তি, অশুভ শক্তিৰ পৰা ৰক্ষা আৰু জীৱনত ইতিবাচক শক্তিৰ কামনা জড়িত বুলি ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছে।

এইদৰে তিনিটা গাঁঠিয়ে মিলি যেন ভাতৃৰ জীৱনৰ বাবে সৃষ্টি, পালন আৰু সংহাৰৰ শক্তিৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰে।

ধৰ্ম, অৰ্থ আৰু কামৰ সৈতেও সম্পৰ্ক

কেৱল ত্ৰিদেৱৰ সৈতে নহয়, ৰাখীৰ তিনিটা গাঁঠিৰ সৈতে জীৱনৰ তিনিটা পুৰুষাৰ্থ-ধৰ্ম, অৰ্থ আৰু কামৰ সম্পৰ্ক আছে বুলিও ধৰ্মীয় ব্যাখ্যা পোৱা যায়। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জীৱনত নৈতিকতা, সমৃদ্ধি আৰু ইচ্ছাৰ মাজত এক সুস্থ ভাৰসাম্য বজাই ৰখা। কিছুমান ধৰ্মীয় বিশ্বাসত এই তিনিটা গাঁঠিক নৱগ্ৰহৰ অশুভ প্ৰভাৱ শান্ত কৰা আৰু জীৱনত শুভ শক্তি বৃদ্ধিৰ প্ৰতীক হিচাপেও ব্যাখ্যা কৰা হয়।

ৰাখী বান্ধোতে কি কি কথা মনত ৰাখিব ?

পৰম্পৰা অনুসৰি ৰাখী বান্ধোতে শুভ সময়ৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া হয়। বিশেষকৈ ভদ্ৰাকালত ৰাখী বান্ধা উচিত নহয় বুলি ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছে। সেয়ে ৰাখী বন্ধাৰ পূৰ্বে শুভ সময় জানি লোৱাটো ভাল।

ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুসৰি ৰাখী বন্ধাৰ সময়ত ভাতৃৰ মুখ পূব বা উত্তৰ দিশলৈ থকাটো শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। ভগ্নীৰ মুখ পশ্চিম বা দক্ষিণ দিশলৈ থকাৰ পৰম্পৰাও কিছুমান বিশ্বাসত উল্লেখ আছে।

আনহাতে, ক'লা ৰঙৰ পোছাক পৰিহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শও কিছুমান ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত দিয়া হয়। ইয়াৰ আঁৰত ক'লা ৰঙে নেতিবাচক শক্তিৰ প্ৰতীক বহন কৰে বুলি থকা বিশ্বাস জড়িত।

ৰাখীৰ গাঁঠিত লুকাই আছে সম্পৰ্কৰ গভীৰ বাৰ্তা

আচলতে ৰাখীৰ তিনিটা গাঁঠিৰ পৰম্পৰাক কেৱল ধৰ্মীয় আচাৰ হিচাপে চোৱাৰ সলনি ইয়াৰ সামাজিক বাৰ্তাও বুজিব পাৰি। প্ৰথম গাঁঠিত দীৰ্ঘায়ু আৰু স্বাস্থ্য, দ্বিতীয় গাঁঠিত সুখ-সমৃদ্ধি আৰু সুৰক্ষা, আৰু তৃতীয় গাঁঠিত শান্তি আৰু মংগলৰ কামনা কৰা হয়।

অৰ্থাৎ এখন সৰু ৰাখীত বান্ধি দিয়া তিনিটা গাঁঠিৰ মাজেৰে ভগ্নীয়ে ভাতৃৰ বাবে এক সম্পূৰ্ণ জীৱনৰ কামনাই আগবঢ়ায়-সুস্থতা, সমৃদ্ধি আৰু শান্তি।

ৰক্ষাবন্ধনৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্যও ইয়াতেই-এডাল সূতা সৰু হ'লেও ইয়াৰ সৈতে জড়িত থাকে মৰম, বিশ্বাস, দায়িত্ব, সুৰক্ষা আৰু আজীৱন সম্পৰ্কৰ এক গভীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।

বিদেশতো 'টক্সিক'ৰ তাণ্ডৱ, দুদিনতে ১৯০ কোটিৰ ব্যৱসায়

জন জন বিচাৰ
...মনোৰঞ্জন ডেস্ক

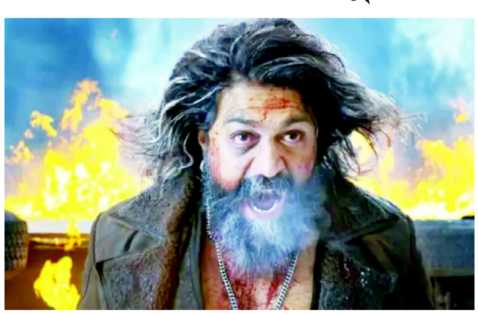

কন্নড় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ৰকিং ষ্টাৰ যশ অভিনীত 'টক্সিক' ছবিখনে মুক্তিৰ পিছৰে পৰা বিশ্বজুৰি বক্স অফিচত চমক সৃষ্টি কৰিছে। ২৬ আগষ্টত ছবিখন ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ পিছত প্ৰথম দিনাই প্ৰায় ১৫০ কোটি টকাৰ বিশ্বজুৰি ব্যৱসায় কৰি শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰে। দ্বিতীয় দিনতো ছবিখনৰ উপাৰ্জনৰ গতি বিশেষ হ্ৰাস পোৱা নাই।

উপলব্ধ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, দ্বিতীয় দিনা 'টক্সিক'এ বিশ্বজুৰি প্ৰায় ৪০ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে। ইয়াৰ ফলত দুদিনত ছবিখনৰ মুঠ বিশ্বজুৰি ব্যৱসায় প্ৰায় ১৯০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। চূড়ান্ত হিচাপ প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত ছবিখনে ২০০ কোটিৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনাও আছে।

বিদেশত যশৰ ছবিৰ বিশেষ দপদপনি

'টক্সিক'ৰ প্ৰতি বিদেশী দৰ্শকৰ আগ্ৰহো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। ছবিখনৰ দুদিনৰ বিদেশৰ বজাৰৰ উপাৰ্জন প্ৰায় ২৬.২৫ কোটি টকা হোৱা বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে।

ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে ছবিখন কেৱল ভাৰতীয় বজাৰতেই নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতো যশৰ জনপ্ৰিয়তাক ব্যৱহাৰ কৰি শক্তিশালী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

প্ৰথম দিনৰ উপাৰ্জনত পিছ পেলালে কেইবাখনো ডাঙৰ ছবিক

প্ৰথম দিনাই প্ৰায় ১৫০ কোটি টকাৰ বিশ্বজুৰি ব্যৱসায়ে 'টক্সিক'ক ভাৰতীয় ছবিৰ অন্যতম বৃহৎ উদ্বোধনী উপাৰ্জনৰ তালিকাত স্থান দিছে।

ছবিখনে প্ৰথম দিনৰ বিশ্বজুৰি উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত 'জৱান'ৰ ১২৯ কোটি, 'এনিমেল'ৰ ১৬ কোটি আৰু 'পাঠান'ৰ ১০৬ কোটি টকাৰ উদ্বোধনী ব্যৱসায়ক পিছ পেলাইছে বুলি প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে। একেদৰে 'আদিপুৰুষ'ৰ ১৪০.৭৫ কোটি টকাৰ প্ৰথম দিনৰ বিশ্বজুৰি ব্যৱসায়কো 'টক্সিক'এ অতিক্ৰম কৰিছে।

অৰ্থাৎ মুক্তিৰ প্ৰথম দুদিনতেই ছবিখনে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ কেইবাখনো চৰ্চিত ছবিৰ উদ্বোধনী ব্যৱসায়ৰ অভিলেখক চেলেঞ্জ জনাইছে।

সমালোচনাত মিশ্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, দৰ্শকৰ মাজত উৎসাহ

ছবিখনক লৈ সমালোচকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া একেবাৰে একমুখী নহ'লেও বক্স অফিচৰ পৰিসংখ্যাই দৰ্শকৰ মাজত ছবিখনৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ স্পষ্ট ইংগিত দিছে। বিশেষকৈ যশৰ একচন-ভিত্তিক পৰ্দা উপস্থিতি আৰু ছবিখনৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ উপস্থাপনে অনুৰাগীৰ মাজত উৎসাহ সৃষ্টি কৰিছে।

ভাৰতত হিন্দী আৰু কন্নড় ভাষাতো ছবিখনে ভাল ব্যৱসায় কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে।

২০০ কোটিৰ দুৱাৰত 'টক্সিক'

মাত্ৰ দুদিনতে প্ৰায় ১৯০ কোটি টকাৰ বিশ্বজুৰি ব্যৱসায়ে 'টক্সিক'ক ২০০ কোটিৰ একেবাৰে ওচৰলৈ লৈ গৈছে। এতিয়া তৃতীয় দিন আৰু আগন্তুক সপ্তাহান্তত ছবিখনৰ ব্যৱসায়ে কিমান গতি লাভ কৰে, সেয়াই হ'ব লক্ষ্যণীয়।

যশৰ 'টক্সিক'ৰ বাবে এতিয়া প্ৰশ্ন কেৱল ২০০ কোটি কেতিয়া পাৰ কৰিব সেইটো নহয়-এই গতি অব্যাহত থাকিলে ছবিখনে বিশ্বজুৰি আৰু কিমান ডাঙৰ বক্স অফিচ অভিলেখ গঢ়ে, সেয়াহে হ'ব পৰৱৰ্তী ডাঙৰ প্ৰশ্ন।

VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

JAN JAN VICHAR

Guwahati, Friday, 28 August 2026

MODI–PUTIN–XI: TWO MAJOR SUMMITS, ONE BIG MESSAGE TO THE WORLD

Jan Jan Vichar
...✍New Delhi

Prime Minister Narendra Modi is set to enter a crucial phase of high-stakes diplomacy, with India preparing to host and participate in major international engagements that could put Modi, Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping together on two important platforms within a short span of time.

Modi's upcoming visit to Uzbekistan and participation in the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Bishkek on August 31–September 1 comes at a time when Central Asia is emerging as an increasingly important arena of global strategic competition. China is expanding its influence through the Belt and Road Initiative, Russia continues to regard the region as part of its traditional strategic sphere, while the United States is seeking to maintain its geopolitical reach.

For India, the message is clear: New Delhi intends to pursue its interests without being locked into any single power bloc.

Uzbekistan holds particular importance in India's Central Asia strategy. Trade, defence, investment, connectivity, digital technology, energy and critical minerals are expected to remain key areas of cooperation. India's efforts to strengthen the International North-South Transport Corridor and its interests in Iran's Chabahar port also underline the urgency of developing alternative routes to Central Asia, especially when traditional land connectivity remains constrained.

Afghanistan and regional security are likely to feature prominently in discussions as well. A stable Afghanistan is vital for expanding trade, connectivity and economic cooperation between South and Central Asia.

The SCO summit will provide Modi an opportunity for direct engagement with Putin, Xi and other Eurasian leaders. Terrorism, energy security, connectivity and regional stability remain issues of direct importance to India.

The India-Russia relationship will also remain under the spotlight. Despite pressure from Western countries, India has maintained its engagement with Moscow based on national interests, particularly in energy, defence, fertilisers, trade and strategic cooperation.

The geopolitical significance could become even greater with the BRICS summit in New Delhi on September 12–13. If Modi, Putin and Xi appear together at two major international gatherings within a short period, the optics will carry considerable strategic weight.

This, however, should not be interpreted as the emergence of an India-Russia-China alliance. India and China continue to have serious differences, while Moscow, Beijing and New Delhi have distinct national interests. Yet their engagement reflects the broader transition towards a more multipolar world order.

For Washington, the development could be uncomfortable. Attempts to push countries into rigid geopolitical camps may become increasingly difficult as major powers pursue issue-based partnerships.

For India, the strategy is one of strategic autonomy-cooperate where interests converge, compete where necessary, and avoid becoming dependent on any single power.

From Tashkent to Bishkek and then New Delhi, Modi's diplomatic calendar could reinforce India's emergence as an independent and consequential player in the changing global order.

Dhubri DIG Reviews Security Along India-Bangladesh Border

Jan Jan Vichar
...✍ Dhubri

Security along the India-Bangladesh international border in Assam's Dhubri district came under close review as Deputy Inspector General of Police, Western Range, Yeshe Tsering Gwatso, visited several sensitive border stretches on August 27.

The inspection was aimed at assessing the prevailing security situation, reviewing existing surveillance arrangements and strengthening measures to prevent illegal activities along the international boundary.

During his visit, DIG Gwatso inspected important border locations, including Patamari, Takimari and Sastar Ghat. He took stock of the security arrangements in these areas and reviewed the challenges faced by security personnel in monitoring the border and preventing unauthorised cross-border movement and other illegal activities.

The DIG also interacted with residents living in the border areas to understand their concerns and gather information about local security-related issues. The interaction was seen as an important step towards strengthening cooperation between law-enforcement agencies and communities residing close to the international border.

Gwatso was accompanied by Dhubri Superintendent of Police Debasish Borah, senior officers of the Dhubri Police Administration and representatives of the Border Security Force (BSF). The presence of senior officials from both the state police and BSF underlined the importance of coordinated efforts in maintaining security along the international boundary.

Speaking to the media during the visit, DIG Gwatso appreciated the efforts of Dhubri Police in maintaining security and tackling illegal activities in the border areas. He specifically highlighted the role of the police in combating cattle smuggling and the illegal drug trade, two major challenges faced by law-enforcement agencies in the region.

The border areas of Dhubri require continuous surveillance because of their proximity to Bangladesh and the presence of several vulnerable stretches. Preventing organised smuggling networks and other cross-border illegal activities therefore remains a key security priority for the police and BSF.

Continued on Page 16

Assam CM Highlights Financial Support for Agri-Entrepreneurs and FPOs

Jan Jan Vichar
...✍Guwahati

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has highlighted the financial assistance available to agri-entrepreneurs and Farmer Producer Organisations (FPOs) under two key central government schemes aimed at strengthening agricultural infrastructure and promoting food processing in the state.

In a post on X, the Chief Minister urged eligible entrepreneurs, farmers' organisations and businesses to make use of the Agriculture Infrastructure Fund (AIF) and the Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) scheme to expand their operations and build stronger agricultural and food-processing infrastructure.

Loans Up to 2 Crore Under AIF

Under the Agriculture Infrastructure Fund, eligible beneficiaries can access low-interest loans of up to Rs. 2 crore for developing agricultural infrastructure. The scheme also provides a 3 per cent interest subvention, aimed at reducing the financial burden on eligible borrowers.

The assistance can help entrepreneurs and farmer organisations invest in infrastructure required for improving agricultural supply chains, storage and related activities. Such investments are expected to help reduce post-harvest losses and improve the efficiency of agricultural businesses.

PMFME Offers 35% Capital Subsidy

The PMFME scheme provides additional financial support for the formalisation and expansion of micro food-processing enterprises.

Under the scheme, individual enterprises can receive a 35 per cent capital subsidy of up to Rs.10 lakh. Support is also available for common infrastructure, with assistance of up to Rs. 3 crore.

The scheme is particularly aimed at encouraging the development and formalisation of small food-processing businesses, enabling them to improve production capacity, infrastructure and market access.

Push for Agricultural Value Addition

The Chief Minister's appeal comes against the backdrop of efforts to promote greater value addition in Assam's agricultural sector. Strengthening food-processing facilities can allow farmers and producer organisations to move beyond the sale of raw agricultural products and participate more actively in processing, packaging and marketing. For FPOs and agri-entrepreneurs, access to affordable institutional finance and capital subsidies could help them establish or upgrade facilities and strengthen their operations.

CM Urges Eligible Beneficiaries to Utilise Schemes

Sarma urged eligible businesses and organisations to take advantage of the financial assistance available under the two schemes. The government expects wider utilisation of such programmes to support agricultural entrepreneurship, improve food-processing infrastructure and create stronger links between farmers, producers and markets.

Manipur Contractors Seek Early Completion of PMGSY-III Tender Evaluation

Jan Jan Vichar
...✍Imphal

The All Manipur Contractors Association Forum (AMCAF) has urged the state government to expedite the pending tender evaluation process for works under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III (PMGSY-III) and ensure that eligible local contractors receive due consideration while awarding work orders.

Addressing the media, AMCAF Convenor Thangjam Somarendra said the prolonged delay in the tender process has become a matter of concern for contractors, particularly at a time when several roads across Manipur

are reportedly in poor condition and require urgent improvement.

According to Somarendra, state-based contractors have played a significant role in the implementation of earlier phases of the rural roads programme. He said contractors from Manipur had constructed 1,913 roads and 211 bridges under PMGSY-I and PMGSY-II.

The contractors' forum said the technical evaluation of 96 road works under PMGSY-III, announced on July 31, was expected to be completed within five days. However, the results of the evaluation have reportedly not yet been declared.

AMCAF said the delay is creating uncertainty among local contractors who are awaiting clarity on the allocation of road projects.

The forum has therefore appealed to the Minister of Rural Development and Panchayati Raj to intervene and ensure that the tender evaluation and subsequent work-order process are completed without further delay.

Somarendra also raised concerns over amendments to the Standard Bidding Document (SBD) and certain provisions incorporated by the National Rural Infrastructure Development Agency (NRIDA) in the Notice Inviting Tender (NIT). He alleged that some of the revised eligibility and bidding conditions have made it difficult for contractors based in Manipur to participate effectively in the tender process.

The forum particularly expressed apprehension that if such conditions remain unchanged, PMGSY-III projects in the state could ultimately be awarded to companies and contractors from outside Manipur.

Continued from page 15

Dhubri DIG Reviews...

Officials also stressed the importance of maintaining close coordination between security agencies and people living in border villages. Local residents can play an important role in identifying suspicious movements and reporting illegal activities, particularly in areas where security forces have to monitor large and difficult-to-access stretches.

The DIG's interaction with residents was aimed at improving this communication mechanism and ensuring that local concerns are brought to the attention of the administration.

The visit forms part of the ongoing efforts to strengthen surveillance and security along the India-Bangladesh border in Assam. Increased coordination between the Assam Police, BSF and local communities is expected to help authorities respond more effectively to emerging security challenges.

The inspection also signals continued attention by senior police officials towards vulnerable border areas, with a particular emphasis on preventing cross-border crime, cattle smuggling, drug trafficking and other illegal activities. As security agencies continue to strengthen their presence and surveillance along the international border, closer cooperation between the police, BSF and border communities is likely to remain crucial for maintaining peace and security in Dhubri district.

Pakistan Weighs Constitutional Status Change for PoK and Gilgit-Baltistan

Jan Jan Vichar
...Islamabad

Pakistan is reportedly considering changes to the constitutional and political status of Pakistan-occupied Kashmir (PoK) and Gilgit-Baltistan, amid growing attention in Islamabad to the evolving relationship between India and China and their ongoing efforts to address the border dispute.

According to reports citing Pakistani government officials, the Shehbaz Sharif government is examining the possibility of introducing a new constitutional framework under which PoK and Gilgit-Baltistan could receive an interim provincial status. The proposed changes could reportedly be introduced through a future constitutional amendment or other legislation.

The development comes as Pakistan closely monitors recent diplomatic engagement between New Delhi and Beijing, particularly the meeting between Indian National Security Adviser Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing. The talks focused on maintaining dialogue and addressing outstanding issues along the India-China boundary.

Islamabad is concerned that any significant progress between India and China on their disputed boundary could have wider implications for the territorial and political situation involving Jammu and Kashmir. China controls Aksai Chin, while Pakistan administers PoK and Gilgit-Baltistan. Pakistan also transferred the Shaksgam Valley to China under the 1963 China-Pakistan Boundary Agreement, a move that India has rejected.

Any future understanding between India and China over their boundary could therefore have consequences for the broader regional strategic landscape.

Reports suggest that Pakistan may examine changes to Article 1(2) of its Constitution, which defines the territories forming part of Pakistan. Islamabad could also consider changes through a proposed constitutional amendment or another legal mechanism.

The reported objective would be to provide PoK and Gilgit-Baltistan with a status closer to that of provinces while maintaining Pakistan's stated position on the Kashmir dispute. Pakistan officially refers to PoK as "Azad Jammu and Kashmir" and has historically maintained that the final status of Jammu and Kashmir remains disputed.

Gilgit-Baltistan is particularly important because of its geographical location and its connection with China's Xinjiang region. The area is also strategically significant for the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and wider Chinese infrastructure and connectivity projects. Granting the region a more formal constitutional status could therefore have implications beyond domestic politics, including for Pakistan's relationship with China and its long-term approach to regional connectivity.

Pakistan's reported consideration of the move appears to be closely linked to changing geopolitical circumstances. While China continues to maintain a strategic partnership with Islamabad, Beijing has also been working to stabilise and improve practical relations with New Delhi.

For Islamabad, any India-China agreement that changes the existing strategic balance in the Himalayan region could potentially affect Pakistan's position on Kashmir. However, whether Pakistan ultimately proceeds with constitutional changes remains uncertain. Any such move would have significant legal, political and diplomatic consequences and could trigger strong reactions from India.

The reported debate nevertheless highlights how closely Pakistan is watching the India-China diplomatic process and how developments along one disputed frontier could increasingly influence the wider geopolitics of Jammu and Kashmir, China-Pakistan relations and South Asia.

RESERVATION : MANJHI DEMANDS REVIEW AND 'QUOTA WITHIN QUOTA

PATNA: The debate over reservation has triggered a fresh political confrontation between two prominent Dalit leaders of the NDA, with Union Ministers Jitan Ram Manjhi and Chirag Paswan taking sharply different positions on the question of reviewing the reservation system and introducing sub-classification within reserved categories.

Manjhi has openly advocated a review of the existing reservation framework and called for a "quota within quota" system, arguing that the benefits of reservation are not reaching the most disadvantaged sections of the Scheduled Castes equally.

His remarks came after Chirag Paswan strongly opposed any proposal to review reservation. Paswan has maintained that reservation is not a government favour or charity but a constitutional right, and has argued that even discussing its abolition or review is unacceptable

Manjhi argued that some sections within reserved communities have made significant social and educational progress over the years, with their children gaining greater access to education, government employment and other opportunities. At the same time, he said, extremely disadvantaged sections continue to face low literacy and limited access to the benefits of reservation.

According to Manjhi, a review of the system should therefore focus not on ending reservation but on ensuring that its benefits are distributed more equitably among different communities within the reserved categories. He has advocated the implementation of sub-classification within reservation, citing Supreme Court directions and the examples of states such as Punjab and Haryana.

The central argument behind sub-classification is that certain relatively advanced groups within reserved categories may have captured a disproportionately large share of available opportunities, while the most deprived groups continue to remain underrepresented.

Manjhi has claimed that before sub-classification, a limited number of dominant communities were receiving a very large proportion of reserved opportunities. He argues that dividing the quota among different subgroups can provide greater representation to communities that have historically received fewer benefits. He has therefore urged the Bihar government to consider such a mechanism within the framework permitted by the Supreme Court.

Chirag Paswan, however, has rejected the idea that reservation should be subjected to a review in a manner that could weaken the existing constitutional safeguards. His position is that reservation represents a constitutional guarantee designed to address historical social discrimination and inequality. According to Paswan, describing reservation as "charity" or questioning its continuation undermines the very principle of social justice for which the system was created.

EDITORIAL

Women's Empowerment

Bihar Chief Minister Samrat Choudhary's Raksha Bandhan announcements, particularly the target of creating direct employment opportunities for one crore women, have the potential to become a significant milestone in the state's development story. The proposed women's university and the plan to connect around 10 lakh Jeevika families with rooftop solar power are equally ambitious. But ambitious targets must ultimately be judged by implementation, not headlines. Bihar has already witnessed the growing economic participation of women through Jeevika and other self-help group initiatives. The claim that around 50 lakh women have become "Lakhpati Didis" reflects the possibilities created when women receive access to finance, skills and markets. Yet millions of women still remain outside stable employment, formal credit and quality higher education.

The government's one-crore employment target therefore deserves both appreciation and scrutiny. Direct employment cannot mean merely distributing subsidies or linking women with short-term schemes. It must create sustainable livelihoods, regular incomes, market access and opportunities for entrepreneurship. The government should publish clear annual targets, district-wise data and independent assessments so that citizens can measure actual progress.

The proposed women's university could also become a transformative institution, provided it offers quality education, research, professional courses and genuine leadership opportunities rather than becoming another symbolic project. Likewise, installing solar panels for Jeevika households can reduce electricity costs and promote clean energy, but transparency in beneficiary selection, installation and maintenance will be essential. Women's empowerment is not a Raksha Bandhan gift. It is a long-term economic and social commitment.

How a 24-hour delay explains the India-China dynamic

Jan Jan Vichar
...✍ C. Uday Bhaskar

On the evening of August 25, after NSA Ajit Doval met Foreign Minister Wang Yi in Beijing for the 25th Round of Special Representatives (SR) talks, the Indian Embassy posted on X that both sides had "reviewed bilateral ties and discussed ways to further expand cooperation and maintain stability." Beijing's version was warmer: Wang Yi and Doval had "comprehensive, in-depth, friendly and candid" discussions and China-India ties now had "global and strategic significance."

But the absence of a joint statement led to speculation that semantic consensus on how to frame contentious issues remained elusive. However, on August 26, an identical eight-point joint consensus was released, first by New Delhi and later by Beijing. The latest statement included a push for an 'Early and Substantial Harvest' on boundary delimitation, two new military meeting points, two new border hotlines in the Eastern and Middle sectors, an Expert-Level Mechanism on trans-border rivers in September, facilitation of Kailash-Mansarovar Yatra, resumption of border trade and the next SR round in India in 2027.

This delay is perhaps the clearest expression of what defines the India-China relationship today: Deeply embedded wariness.

A joint statement after SR talks is rare. This time, an eight-point text was actually agreed within 18 hours, which signals political intent at the highest level to lock in stability ahead of a packed fortnight: The SCO summit in Bishkek and the BRICS summit in New Delhi on September 12.

But the language adopted shows how complex this task is when dealing with a tangled bilateral relationship where contested territoriality and deeply embedded suspicion are at the core.

'Early and Substantial Harvest' is not a casual phrase. It was coined during talks in 2024 and 2025 to denote progress on delimitation, mapping where the border is, without prejudice to final settlement under the 2005 Agreement on Political Parameters.

Agreeing to two additional hotlines and meeting points in the Eastern and Middle sectors (Eastern refers to Arunachal Pradesh, Middle means Himachal and Uttarakhand) is operationally significant. Until now, the only functional hotline was in the Western sector, Ladakh.

For Beijing to accept new military CBMs in the Eastern sector, which it claims as South Tibet, would have required internal clearance, that the new mechanism does not amount to recognition of the LAC. That is why the joint text carefully says "improving understanding of LAC in appropriate areas" and "promptly address situations through existing diplomatic and military channels to avoid misunderstanding and miscalculation" - classic wariness vocabulary.

The wariness extends to nomenclature. In the joint statement, both sides avoided the word Tibet/ Xizang altogether, referring only to "Kailash-Mansarovar Yatra" and "border trade through three passes."

When they must sign jointly, they simply omit the contentious noun and keep the dual mountain-lake names- Kailash and Gang Rinpoche, Manasarovar and Mapam Yun Tso - as a linguistic buffer.

India as chair needs a successful BRICS summit. China has publicly said it "supports India in hosting a successful BRICS summit" but as of late August, remains evasive regarding the participation of President Xi Jinping. The official response from Beijing is "no information to share" on whether Xi will attend. It is calibrated tactical ambiguity, to keep Delhi anxious and not to commit early.

India has to accept this kind of ambiguity given its current vulnerability on the trade-economic front and the prevailing Trump-triggered geopolitical turbulence. The Doval visit has led to a deft outcome, wherein Delhi can highlight difficult bilateral issues even while nurturing BRICS as a multipolar platform.

The 24-hour gap between separate and joint statements is that deftness in miniature: Separate texts to protect domestic optics, agree together after overnight vetting by the top leadership and choose words so carefully that even a mountain has two names. Wariness is not the failure of diplomacy. In India-China ties, it is the method.

The writer is director, Society for Policy Studies, New Delhi

मानक हिन्दी वर्तनी : व्याकरणिक सूक्ष्मताएं और सटीक शब्द-चयन

जन जन विचार

...✍ डॉ मुकेश कुमार

हिंदी संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक भाषाओं में से एक मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैसा स्पष्ट उच्चारण किया जाता है, वैसा ही सटीक लेखन भी किया जाता है। हालांकि, इसी विशेषता के कारण जब उच्चारण में सूक्ष्म-सी लापरवाही होती है, तो लेखन में भी गंभीर अशुद्धियां आ जाती हैं।

हिंदी के विद्यार्थियों व पाठकों के लिए कई बार मिलते-जुलते शब्द भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। एक छोटी-सी मात्रा या बिंदी (अनुस्वार) का हेर-फेर पूरे वाक्य के अर्थ को उलट-पुलट सकता है। इस आलेख में दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले प्रमुख व्याकरणिक शब्दों के अंतर, उनके सटीक नियमों और उदाहरणों का अत्यंत सरल एवं व्यावहारिक भाषा में विस्तृत अध्ययन किया है, जो इस प्रकार से है -

1. 'और' तथा 'ओर' का भेद: योजक बनाम दिशा

लेखन में अक्सर 'और' की जगह 'ओर' या 'ओर' की जगह 'और' लिख दिया जाता है। यद्यपि दोनों शब्दों में केवल एक मात्रा का अंतर दिखाई देता है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से दोनों के कार्य बिल्कुल भिन्न हैं।

'और' (योजक शब्द) : यह एक योजक (समुच्चयबोधक) शब्द है। इसका मुख्य कार्य दो शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ना होता है।

नियम : जब आपको दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या क्रियाओं को एक साथ शामिल करना हो, तब 'और' का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए -

सीता और गीता अच्छी मित्र हैं,

मुझे एक कलम और एक उत्तर-पुस्तिका चाहिए।

उसने खाना खाया और सो गया।

'ओर' (दिशा सूचक शब्द) : यह शब्द किसी दिशा, तरफ, लक्ष्य या संकेत को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

नियम : जब आप किसी स्थान या व्यक्ति की तरफ बढ़ने या देखने की बात कर रहे हों, तब 'ओर' शब्द का प्रयोग होता है।

उदाहरण देखिए -

सूर्य पूर्व की ओर उगता है।

वह विद्यालय की ओर जा रहा है।

उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिया।

याद रखने का सहज तरीका :- यदि आपको जोड़ने का काम करना हो, तो दो मात्राओं वाले 'और' का प्रयोग करें। यदि आपको किसी तरफ जाने या देखने की बात करनी हो, तो एक मात्रा वाले 'ओर' का प्रयोग करें।

2. 'की' तथा 'कि' का अंतर : संबंध कारक बनाम वाक्य योजक

यह हिंदी लेखन की सबसे अधिक होने वाली अशुद्धि है। कक्षा दसवीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षाओं में 'की' और 'कि' के प्रयोग से जुड़ी अशुद्धियां सर्वाधिक देखी जाती हैं।

'की' (दीर्घ ई - बड़ी मात्रा) : यह संबंध कारक का रूप है। यह दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच मालिकाना हक, अधिकार या संबंध स्थापित करती है।

नियम : 'की' का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग शब्दों से ठीक पहले या उनके संबंध में होता है। इसके अतिरिक्त, भूतकाल की 'करना' क्रिया के स्त्रीलिंग रूप के लिए भी 'की' लिखा जाता है। उदाहरण (संबंध कारक)- यह राम की किताब है। (यहां 'किताब' स्त्रीलिंग है, इसलिए 'की' आया),

भारत की संस्कृति प्राचीन और महान है।

व्यावहारिक उदाहरण (क्रिया रूप): उसने आज बहुत मेहनत की।

'कि' (ह्रस्व इ - छोटी मात्रा): यह एक व्यधिकरण समुच्चयबोधक (योजक) है। यह दो अलग-अलग वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है।

नियम : जब कोई बात कही जाती है, सोची जाती है या किसी कारण का उल्लेख किया जाता है, तो मुख्य वाक्य को गौण वाक्य से जोड़ने के लिए 'कि' का प्रयोग होता है।

व्यावहारिक उदाहरण-

उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा।

अध्यापक ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए।

मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई खड़ा है।

स्मरण सूत्र :

बोलते समय जहां रुककर बात पूरी की जाती है या बात को आगे बढ़ाया जाता है, वहां तुरंत बोली जाने वाली छोटी 'कि' लगती है। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध दर्शाया जाता है, वहां खींचकर बोली जाने वाली बड़ी 'की' लगती है।

3. 'में' तथा 'मैं' का अंतर : स्थान का बोध बनाम आत्म-बोध

मात्रा के साथ लगी बिंदी (अनुस्वार) और ऐ की मात्रा का अंतर पूरे अर्थ को बदल देता है।

'में' (अधिकरण कारक) : यह शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के किसी सीमा, स्थान या स्थिति के 'अंदर' या 'भीतर' होने का बोध कराता है।

नियम : स्थान, समय, सीमा या दायरे को दर्शाने के लिए 'में' का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए-

बच्चे कक्षा में शांति से बैठे हैं।

थैले में ताजे फल रखे हैं।

इस पुस्तक में बहुत सुंदर कहानियां हैं।

'मैं' (उत्तम पुरुष सर्वनाम) : यह शब्द स्वयं (खुद) के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम है।

नियम : जब बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में कोई बात करता है, तब 'मैं' का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए -

मैं प्रतिदिन प्रात:काल टहलने जाता हूं।

मैं दसवीं कक्षा का छात्र हूं।

मैं भारत देश का निवासी हूं।

पहचान कैसे करनी है देखिए -

अगर बात अपने स्वयं के बारे में हो रही है तो दो मात्राओं वाला 'मैं' प्रयोग करें। अगर बात किसी चीज के अंदर होने की हो रही है तो एक मात्रा वाला 'में' प्रयोग करें।

4. मानक शब्द बनाम अशुद्ध शब्द: 'सकता' और 'शकता'

अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्राय: क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण 'स' और 'श' के उच्चारण में मिलावट हो जाती है। इसके कारण लेखन में भी अशुद्धियां आ जाती हैं।

'सकता' (मानक एवं शुद्ध रूप) : यह हिंदी व्याकरण का एक प्रामाणिक सहायक क्रिया रूप है, जो किसी कार्य को करने की क्षमता, योग्यता या संभावना को दर्शाता है। उदाहरण देखिए-

मैं यह भारी बक्सा आसानी से उठा सकता हूँ। (क्षमता)

क्या आप यह पाठ दोबारा समझा सकते हैं? (योग्यता/विनम्रता)

आज शाम को वर्षा हो सकती है (संभावना)।

'शकता' (अमानक एवं अशुद्ध रूप) : हिंदी मानक व्याकरण में 'शकता' नाम का कोई शब्द अस्तित्व में नहीं है। यह केवल गलत उच्चारण (जैसे 'स' की जगह 'श' बोलना) का परिणाम है।

अशुद्ध : मैं यह काम कर शकता हूँ।

शुद्ध वाक्य : मैं यह काम कर सकता हूँ।

विशेष सुझाव : अहिंदी भाषी छात्रों को 'स' (दन्त्य) और 'श' (तालव्य) की ध्वनि का अभ्यास करना चाहिए, ताकि लिखते समय ऐसी त्रुटियाँ न हों।

5. शिष्टाचार और आवश्यकता : 'कृपया' तथा 'चाहिए'

भाषा में मधुरता और शुद्धता बनाए रखने के लिए उपयुक्त शब्दों का चुनाव अत्यंत आवश्यक है।

'कृपया' (विनम्रता सूचक शब्द) : यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम किसी से अनुरोध करते समय, सहायता मांगते समय या शिष्टाचार प्रदर्शित करते समय करते हैं।

नियम : कई लोग इसे 'कृपा' लिख देते हैं जो कि अशुद्ध है। 'कृपया' शब्द का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में या क्रिया से पूर्व विनम्रता दर्शाने के लिए होता है।

उदाहरण देखिए -

कृपया अपनी पुस्तक मुझे दीजिए।

कृपया यहां शांति बनाए रखें।

'चाहिए' (आवश्यकता एवं कर्तव्य सूचक) : यह शब्द दो प्रमुख स्थितियों में प्रयुक्त होता है-पहला किसी वस्तु की आवश्यकता दर्शाने के लिए, और दूसरा किसी नैतिक कर्तव्य या परामर्श को व्यक्त करने के लिए।

नियम : इसका प्रयोग कभी भी 'चाहीए' या 'चाहिये' के रूप में नहीं करना चाहिए। मानक वर्तनी 'चाहिए' ही है।

उदाहरण देखिए-

(नैतिक कर्तव्य/परामर्श) :

हमें सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए।

विद्यार्थियों को प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए।

व्यावहारिक उदाहरण (आवश्यकता)

मुझे पढ़ने के लिए एक शांत स्थान चाहिए।

6. स्थान और पुनरावृत्ति : 'यहाँ / वहाँ' तथा 'दोबारा'

वाक्य गठन में स्थानवाचक अव्यय और क्रियाविशेषणों का सही स्थान समझना अति आवश्यक है।

'यहाँ' और 'वहाँ' (स्थानवाचक क्रियाविशेषण) : ये दोनों शब्द स्थानों का बोध कराते हैं।

यहाँ : यह वक्ता (बोलने वाले) के समीप या पास के स्थान का संकेत देता है।

वहाँ : यह वक्ता से दूर के स्थान का संकेत देता है। उदाहरण देखिए -

आप यहाँ आकर बैठिए। (समीप)

वह वहाँ मैदान में खेल रहा है। (दूर)

'दोबारा' (पुनरावृत्ति सूचक शब्द) : जब कोई कार्य एक बार होने के बाद पुन: या फिर से किया जाता है, तो उसके लिए मानक शब्द 'दोबारा' का प्रयोग किया जाता है।

नियम : क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाववश कुछ लोग 'दुबारा' या 'दुबारा से' बोलते हैं, परंतु मानक हिंदी में 'दोबारा' शब्द ही पूर्णत: शुद्ध माना जाता है। उदाहरण देखिए -

इस पाठ को दोबारा पढ़ो ताकि सब समझ आ जाए।

मुझसे वही भूल दोबारा नहीं होगी।

छात्रों के लिए विशेष अभ्यास युक्तियां

विद्यार्थियों और नए पाठकों को हिंदी व्याकरण पर सहज पकड़ बनाने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक उपायों को अपनाना चाहिए ,जो इस प्रकार से है-

सस्वर वाचन (जोर से पढ़ना) : जब आप पाठ्यपुस्तक को जोर से पढ़ते हैं, तो 'की' और 'कि' के उच्चारण का अंतर आपके कानों को समझ आने लगता है। 'की' पर थोड़ा बल दिया जाता है जबकि 'कि' को बिना रुके तुरंत बोला जाता है।

मात्राओं पर ध्यान देना : 'में' और 'मैं' का अंतर समझने के लिए वाक्य के अर्थ पर ध्यान दें। यदि वाक्य किसी व्यक्ति के 'अंदर' होने की बात कर रहा है, तो एक मात्रा का प्रयोग करें। यदि वाक्य आपके 'स्वयं' के बारे में है, तो दो मात्राओं का प्रयोग करें।

मानक शब्दावली का प्रयोग : बोलचाल की प्रादेशिक अशुद्धियों (जैसे 'सकता' की जगह 'शकता' बोलना) को दूर करने के लिए शब्दकोश और मानक समाचार-पत्रों का नियमित पठन करें।

लेखन अभ्यास : प्रतिदिन 5 से 10 वाक्य ऐसे लिखें जिनमें इन भ्रम पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ हो। सहपाठियों या शिक्षकों से उन वाक्यों की जाँच कराएँ। बार -बार अभ्यास करने ,लेखन करने से ही भाषा लेखन में शुद्धता आती है।

यदि छात्र और पाठक इन आधारभूत व्याकरणिक नियमों को रटने के स्थान पर उनके व्यावहारिक अर्थ को समझकर प्रयोग करेंगे, तो हिंदी भाषा में लेखन और सम्प्रेषण दोनों अत्यंत सहज, सरस और त्रुटिहीन हो जाएंगे।

Bollywood's Heartwarming Raksha Bandhan Bonds

Jan Jan Vichar
...✍New Delhi

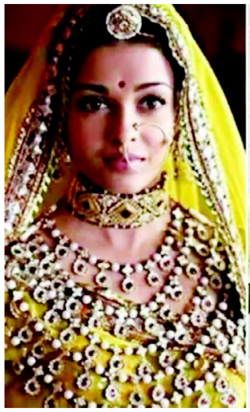

Raksha Bandhan celebrates a bond built on love, trust and protection-and that bond does not always require a blood connection. Bollywood and television have several heartwarming examples of "chosen" brothers and sisters who have remained close long after their professional associations ended.

From co-stars who played siblings on screen to friendships that gradually turned into family-like relationships, these bonds show that sometimes relationships are created not by birth, but by the affection people share.

Aishwarya Rai and Sonu Sood

Aishwarya Rai Bachchan and Sonu Sood developed a special bond while working together in Ashutosh Gowariker's 2008 period drama Jodhaa Akbar. Aishwarya played Jodhaa, while Sonu portrayed her brother Sujamal. Their on-screen relationship reportedly grew into a warm off-screen bond, with Aishwarya celebrating Raksha Bandhan with Sonu.

Ashnoor Kaur and Rohan Mehra

Their brother-sister relationship began on the television set of Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Although the show ended, their friendship continued. The two have remained connected and celebrate Raksha Bandhan together, with Rohan also showing his support for Ashnoor during her Bigg Boss journey.

Deepika Padukone and Jalal

Deepika Padukone does not have a brother, but she has found a brother-like figure in her longtime bodyguard Jalal. Known for accompanying the actress almost everywhere, Jalal shares a close bond with Deepika and her family. The actress has publicly spoken about tying a rakhi to him.

Nia Sharma and Krystle D'Souza

Nia Sharma and Krystle D'Souza became close while working together on Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai. Their professional association developed into a lasting friendship, and Nia has continued the tradition of celebrating Raksha Bandhan with Krystle.

Gauri Khan and Sajid Khan

Gauri Khan shares a brother-sister-like relationship with filmmaker Sajid Khan. The connection has been strengthened by the close friendship between Shah Rukh Khan and Farah Khan and the warmth shared between their families.

Katrina Kaif and Arjun Kapoor

Katrina Kaif and Arjun Kapoor have shared a strong friendship for years. Katrina has herself revealed that she ties a rakhi to Arjun, making their relationship another example of a bond that goes beyond conventional family ties.

Amrita Arora and Arbaaz Khan

Even after the marriage of Malaika Arora and Arbaaz Khan ended, Amrita Arora has maintained a warm relationship with Arbaaz. As someone who does not have a biological brother, Amrita has continued the Raksha Bandhan tradition with her former brother-in-law.

Bhojpuri Stars Celebrate the Festival of Sibling Love on 'Bhojpuri Bawaal'

Jan Jan Vichar
...✍Entertainment Desk

The spirit of Raksha Bandhan came alive on the reality show Bhojpuri Bawaal, as several popular Bhojpuri celebrities celebrated the festival of sibling love and family bonding. With stars such as Amrapali Dubey, Khesari Lal Yadav, Kajal Raghwani, Dinesh Lal Yadav, Rani Chatterjee and Pawan Singh participating in the show, the special Raksha Bandhan episode brought an emotional family touch to the reality programme.

A promotional video shows the celebrities observing the festival and highlighting the emotional bond between brothers and sisters. The theme of the celebration was centred on the idea that Raksha Bandhan is not merely a ritual but an occasion for families to come together and strengthen their relationships. Amrapali Dubey was seen tying a Rakhi to her sister. During the emotional moment, she expressed her affection by praying that she would continue to have her sister as her sibling in every lifetime. Her heartfelt words added an emotional dimension to the celebrations.

Khesari Lal Yadav also spoke about his personal tradition of celebrating Raksha Bandhan. He revealed that regardless of where he may be working or staying, he makes it a point to return to his village for the festival.

Printed & Published by Purvanchal Prints, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati-781005 Contact: 69001 26012
Email : Official.janjanvichar@gmail.com, Website : www.janjanvichar.in ● Executive Editor : Subhash Kumar Choudhary ● Editor : Dhaneshwar Choudhary